स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–20, अंक–3, फाल्गुन–चैत्र 2068–69, मार्च 2012

सम्पादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

अनुक्रम

आवरण लेख
खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर राष्ट्रीय सम्मेलन /4

अर्थव्यवस्था
वित्तीय घाटे पर नियंत्रण के उपाय
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /10

दृष्टिकोण
सरकारी कर्ज के भंवर से बचे भारत
– डॉ. अश्विनी महाजन /12

सामयिकी
तेल के लिए खेल
– निरंकार सिंह /15

विचार–विमर्श
घटता निर्यात – चिंता का विषय
– जयंतीलाल भंडारी /18

अंतर्राष्ट्रीय : ईरान–इजरायल के बीच फंसा भारत
– बालेन्दु शर्मा 'दाधीच' /21

मुद्दा
केन्द्रीय नीति में राज्यों की सहमति जरूरी
– जवाहरलाल कौल /23

अधिकार
जनता के हक पर मोहर
– अरुण जेटली /26

पर्यावरण
हिमालय का विनाशकारी दोहन
– उमेश प्रसाद सिंह /28

यात्रा
भारत की आत्मा गाँव है एवं गाँव की आत्मा कृषक
– डॉ. नन्द सिंह नरूका /31

लेख
महिला शिक्षा और विकास
– रेणु पुराणिक /33

पाठकनामा / 2, रपट / 36

पाठकनामा

हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना होगा

स्वदेशी पत्रिका का फरवरी अंक पढ़ने को मिला बहुत ही पसंद इसलिए आया कि यह पत्रिका हमारी देश की संस्कृति, सभ्यता व नैतिक शिक्षा के साथ–साथ आज की समस्याएं जैसे – पर्यावरण, भ्रष्ट तंत्र और इसके अतिरिक्त जीवन के सभी पहलुओं पर निरंतर प्रकाश डालती रहती है। आज हर नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है साथ ही हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उसे प्रकृति का दोहन अपनी भोगविलासता के लिए नहीं उपयोग करना चाहिए। अब समय आ गया है कि मानव ने जितना प्रकृति का विनाश किया उसे सुधारने का कार्य करना चाहिए जैसे आवश्यकता से अधिक वाहन न रखना, जनसंख्या पर नियंत्रण रखना, पेड़ का संरक्षण के साथ साथ पेड़ लगाना, शहरों में बढ़ती जमीनी भूख को कम करना। इसके अलावा आज के हर व्यक्ति को अपनी भोग–विलासिता की भूख को छोड़ना होगा अन्यथा कही ऐसा न हो जाए कि मानव मानव का ही दुश्मन बन जाए।

– सुधीर रावत, फैबटेक सर्विस सेन्टर, अभय खण्ड–4, इंदिरापुरम्

राष्ट्रीय स्वाभिमान की सच्ची संवाहिका है स्वदेशी पत्रिका

मुझे स्वदेशी पत्रिका नियमित पढ़ने को मिल रही है। इसमें शामिल लेखों से मैं काफी प्रभावित हूँ। जनवरी 2012 के अंक में कहाँ से लाएगा केन्द्र अनाज, सिर्फ इच्छा नहीं इच्छा शक्ति चाहिए, सबसे बड़ा राजनीतिक छल, घरेलू महिलाओं का अवमूल्यन क्यों? आदि लेख बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा आपने मेरा लेख 'पानी पर सोचने का समय' छापा बहुत अच्छा लगा। स्वदेशी पत्रिका अब गाँव–गाँव तक सरस्वती शिशु मन्दिरों में पहुँच रही है और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि इसकी प्रसार संख्या निरंतर बढ़ती रहे। ताकि राष्ट्रीय स्वाभिमान, आर्थिक स्वावलंबन, राष्ट्रीय जनजागरण में प्रगति आए।

– राजेन्द्र सिंह सोमवंशी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

दागियों से जनता दूर नहीं भागी

जनता चाहे जितनी जागी हो, चुनाव के दौरान अब भी दागियों से दूर नहीं भागी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब और उत्तराखण्ड में भी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लोगों ने जम कर वोट किया। बड़ी संख्या में ये जीते और इनमें से अधिकांश मामूली अंतर से दूसरे या तीसरे नम्बर पर रहे। उत्तराखण्ड में ऐसे दस शीर्ष उम्मीदवारों में से 70 फीसदी व पंजाब के दस शीर्ष उम्मीदवारों में से 50 फीसदी उम्मीदवार चुनाव में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे। वहीं यूपी में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 50 थी जिसमें से 18 ने शानदार जीत दर्ज की। इन परिणामों को देखकर लगता है कि जनता अभी भी आपराधिक और भ्रष्टतंत्र के जाल में फंसी हुई है। इसलिए जनता को जगाने के लिए अभी और मंथन की आवश्यकता है।

– राकेश कुमार दास, मीडिया अपार्टमेंट, इंदिरापुरम

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मद्रोत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता स्वच्छ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

हम एक राष्ट्र के रूप में आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में गंभीर क्यों नहीं, जबकि सब जानते हैं कि आतंक का साया आज देश के लगभग हर राज्य पर मंडराने लगा है?

– जवाहरलाल कौल

उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पर विश्वास किया है और हम जनता के हितों के लिए काम करेंगे।

– अखिलेश यादव

पांच राज्यों के चुनाव नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि केन्द्रीय सत्ता अब राज्यों की अनदेखी नहीं कर सकेगी।

– प्रकाश सिंह बादल

देश में तकनीकी विकास तो हुआ लेकिन खुले में शौच करने का कलंक देश से अब तक नहीं मिटा।

– जयराम रमेश

मनमोहन सिंह सरकार ने अनायास ही अर्थव्यवस्था को गड्ढे में ढकेल दिया है।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

पूंजीवादी पैसे और सत्ता को अपना ईश्वर बना लेता है और फिर उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए लगभग सब कुछ कुर्बान कर देता है।

– निरंकार सिंह

अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल सही कहा है, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हक के लिए इकट्ठा होना और धरने के माध्यम से प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल पहलू है।

– अरुण जेटली

लो शुरू हो गई सप्रंग विघटन की दास्तां

पांच राज्यो के विधानसभा चुनाव परिणाम ने देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि बजट बाद राजनीतिक दलों के बीच कुछ नए समीकरण बने। जाहिर है इस नए समीकरण में कांग्रेस का सबसे अधिक नुकसान हो सकता है। क्योंकि सोनिया और राहुल गांधी नाम के दो राजनीतिक आइकॉन अपना असर खोने लगे है। यूपीए में शामिल क्षेत्रीय पार्टिया एक एक कर कांग्रेस से दूरियां बनाने लगी हैं। तमिलनाडू में डीएमके और पश्चिम बंगाल में तृणमूल ने इशारों में नहीं खुलेआम कांग्रेस पर हमले बोल दिए हैं। इन दोनों पार्टियों की चाहत और कोशिश इस बात की है कि अगले किसी भी चुनाव में वे कांग्रेस के साथ न जाएं। इन दोनों पार्टियों के नेता अब कांग्रेस विरोधी राजनीतिक धुरियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ममता बनर्जी पहले भी एनडीए के साथ रह चुकी हैं, इसलिए उनके सम्पर्क सूत्र वहां उनके आने के इंतजार में हैं। डीएमके या एआईडीएमके पाले बदलने में जरा भी देरी नहीं करती। यह जग जाहिर है। अब उत्तरप्रदेश में कांग्रेस की हार ने यूपीए के विघटन की नई पटकथा लिख दी है। अब केंद्र में कांग्रेस को समर्थन जारी रखने की मजबूरी न तो सपा की रही और न बसपा की। सत्ता से बेदखल के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती खुद राज्यसभा में पहुंच कर सरकार की सिरदर्दी बढ़ाने वाली हैं। अब उनके सामने खोने को कुछ भी नहीं है। सीबीआई के जरिए भयादोहन कर अधिक दिनों तक समर्थन नहीं लिया जा सकता। सवा दो सौ विधायकों के साथ मुलायम सिंह इतने मजबूत हो गए हैं कि अब वह खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगे हैं। अपने पुत्र अखिलेश को मुख्यमत्री की कुर्सी सौप वह स्वयं तीसरे मोर्चे को जिंदा करने और लोकसभा चुनाव के मैदान में उसे उतारने की रणनीति पर लग चुके हैं। उनके सक्रिय होने का अर्थ ही हैं कांग्रेस के समर्थक दलों का छिटकना। रही सही कसर इस बार का बजट निकाल देगा। कांग्रेस के पास देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का आखिरी मौका है। पर आकड़े बताते हैं कि सरकार की हालत काफी पतली है। एक तरफ कर उगाही में भारी गिरावट आई है और दूसरी तरफ खर्चे में भारी बढोतरी। यानी घाटा बेशुमार। कांग्रेस के लिए मुसीबत ही यही है। यदि घाटा कम करने का प्रयास करते हैं तो आम जनता की परेशानी काफी बढ़ जाती है और आम जनता को राहत देने का प्रयास करते हैं तो अर्थव्यवस्था की सेहत बिगड़ जाती है। इन दोनों में सामंजस्य बिठाने की हर कोशिश विफल होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अपने लोकलुभावन नारों को चुनाव की बेला में छोड़ना नहीं चाहती, कर्ज माफी और मनरेगा ने वित्तीय संकट बढ़ाने में पूरी भूमिका निभाई है और अब खाद्य सुरक्षा को लेकर वित्तमंत्री की बेचैनी बढ़ गई है। पर कांग्रेस के लिए इन मुद्दों को छोड़ने का विकल्प नहीं बचा है। अगले आम चुनाव में अपनी डूबती नइया को पार लगाने के लिए सोनिया गांधी के तरकश में ये आखिरी तीर हैं। पर ये तीर कहीं गलत निशाने पर न लगे इसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने में लगी है। यहां कांग्रेस और सरकार दोनों के लिए कठिनाइयां है। कुछ दिन थमने के बाद महंगाई फिर बढ़ने लगी है। पीछे महंगाई रोकने के जो उपाय रिजर्व बैंक के जरिए किए गए उसका दुष्परिणाम उद्योग व कॉरपोरेट जगत भुगत रहे हैं। औद्योगिक विकास दर सतह पर आ गई है और कॉरपोरेट जगत पूंजी के लिए ललायित हो रहा है। जाहिर है अब कोई भी कठोर मौद्रिक नीति देश की दशा बिगाड़ सकती है। सब तरफ से राहत की मांग की जा रही है। यदि बजटीय प्रावधानों से स्थिति नहीं सुधरती। आम आदमी का जीवन सरल नहीं होता तो उसका सारा प्रभाव यूपीए के स्थायित्व पर पड़ेगा। राजनीतिक दलों के बीच नए ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। कांग्रेस अपने किए का भर रही है। कुछ समय से नीतियों को लेकर भी यूपीए बटा बटा सा नजर आ रहा है। खास कर खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों को अनुमति देने के राहुल गांधी की जिद ने एक तरह से गठबंधन में दरार डाल दी है। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर तो यूपीए छोड़ने को लगभग तैयार थी। उत्तर प्रदेश में भारी सफलता अर्जित करने वाले मुलायम ने भी कहा था कि यदि वालमार्ट या अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्टोर खुले तो वे आग लगा देंगे। कांग्रेस से छिटकने या उससे समर्थन वापस लेने का सिलसिला चल पड़ेगा। वैसे भी कांग्रेस के घटक दलों के बीच समन्वय नहीं के बराबर है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई तो राहुल गांधी को नेता के रूप में पेश करने की कांग्रेस की कोशिश को विफल माना जाएगा। यानी पवार भी पाला बदल सकते हैं। यूपीए घटक में कांग्रेस के लिए विश्वसनीय साथी का अभी से ही टोटा पड़ने लगा है। जिनको कांग्रेस के साथ चलने की मजबूरी है वे फिलहाल राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं रहे। लालू प्रसाद यादव व अजित सिंह जैसे नेता कांग्रेस के लिए कोई मजबूत विकल्प नहीं है। इनके बूते यूपीए का भविष्य नहीं बन सकता।

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर राष्ट्रीय सम्मेलन

ग्रामीण भारत पहले ही खेती में संकट से जूझ रहा है। भारत की तुलना दूसरे देश से नहीं की जा सकती है क्योंकि यहां 82 प्रतिशत छोटे किसान हैं। इनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है। इनका एक–चौथाई हिस्सा भूखा और बड़ा हिस्सा कुपोषित है। खेती का अर्थव्यवस्था में योगदान 50 प्रतिशत से गिरकर महज 14 प्रतिशत रह गया है जबकि आबादी का 62 प्रतिशत रोजगार अकेले खेती पर ही निर्भर है. ..

भारत के खुदरा कारोबार से जुड़े 31 से ज्यादा संस्थाओं ने एक साथ एक मंच पर एफडीआई का खुदरा कारोबार पर प्रभाव के ऊपर नई दिल्ली के जंतर–मंतर रोड के नजदीक एनडीएमसी कन्वेशन हॉल में 10 फरवरी को आयोजित किया।

अलग–अलग सत्रों में व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स, किसान, यूनियन, और उपभोक्ताओं के अलग–अलग 800 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आयोजन समिति की ओर से सीएआईटी के महासचिव श्री प्रवीण खंडेलवाल ने सभी प्रतिनिधियों का तहे दिल से स्वागत किया। सीपीएम के वरिष्ठ नेता श्री बासुदेव आचार्य ने कन्वेशन का उदघाटन दीप प्रज्ज्वलित करके किया। सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र भाई शाह भी सम्मेलन में मौजूद थे।

प्रारंभिक सत्र के आरंभ में देश के प्रमुख किसान नेता श्री नरेश सिरोही ने कहा कि इस मुददे के महत्व को देखते हुए खुदरा कारोबार से जुड़े हिस्सेदारों ने तय किया है कि इसके लिए एक साझा मुहिम चलाई जाए। खुदरा कारोबार खेती के बाद देश में सबसे बड़ा नियोजक है। देश में किसानों को दी जाने वाली बहुत बड़ी सब्सिडी इस बात का गवाह है कि एफडीआई से किसानों को फायदा नहीं होने वाला है। इससे दुनियाभर के किसान तबाह हो रहे है।

कन्वेशन को संबोधित करते हुए सीपीएम के वरिष्ठ नेता और सांसद श्री बसुदेव आचार्य ने कहा कि यह मुददा सुर्खियों में तब आया जब यूपीए–1 में सरकार ने सिंगल ब्रांड रीटेल में 51 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी थी और सरकार इंश्योरेंस में 49 फीसदी एफडीआई लाने की फिराक में थी। यह फैसला देश के 40 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करने वाला है और इस पर सरकार ने संसद को अंधेरे में रखा। ग्रामीण भारत पहले ही खेती में संकट से जूझ रहा है। भारत की तुलना दूसरे देश से नहीं की जा सकती है क्योंकि यहां 82 प्रतिशत छोटे किसान हैं। इनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है। इनका एक–चौथाई हिस्सा भूखा और बड़ा हिस्सा कुपोषित है। खेती का अर्थव्यवस्था में योगदान 50 प्रतिशत से गिरकर महज 14 प्रतिशत रह गया है जबकि आबादी का 62 प्रतिशत रोजगार अकेले खेती पर ही निर्भर है। भारत की तुलना चीन से नहीं की जा सकती है क्योंकि भारत सरकार का मकसद गरीबों की भलाई करना है। सरकार खुदरा कारोबार में जिसे विदेशी निवेश का हवाला दे रही है वह विश्वास के काबिल नहीं है क्योंकि विदेशी पूंजी को कभी भी वापिस लिया जा सकता है। सरकार तो पहले से ही रोजगार दिला पाने में असमर्थ है और स्व–नियोजित सेक्टर को बर्बाद करने में लगी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में फर्क बढ़ता जा रहा है। पूर्वी एशिया के उदाहरण से भी यह साफ है कि एफडीआई से किसानों का भला नहीं होने वाला है। कॉरपोरेट किसानों को बर्बाद कर देंगे। 1991 के बाद उदारवाद से खेती पहले से ही संकट में है। हमें इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए जन–आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है।

इस संबोधन के साथ ही प्रारंभिक सत्र समाप्त हो गया। इसके बाद आर्थिक सत्र का आरंभ हो गया जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मुरली मनोहर जोशी, फॉरवर्ड ब्लॉक के देबब्रत विश्वास और अमूल के मैनेजिंग डॉयरेक्टर श्री आर. एस सोढी ने हिस्सा लिया।

आर्थिक सत्र

इस विषय पर बहस आरंभ करते हुए

मुंबई के खुदरा व्यापार विशेषज्ञ श्री एस वी फेन ने खुदरा कारोबार में एफडीआई के प्रभाव को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। क्योंकि ये खुदरा कारोबार से जुड़े करोड़ो लोगों के हितों के लिए प्रतिकूल साबित होगा। उन्होंने इस विषय पर किए गए दूसरे देशों के अनुभवों का हवाला दिया जहां कि वैश्विक खुदरा कारोबारी बड़ा कारोबार चला रहे हैं। यह साबित हो चुका है कि बड़ी कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य और संसाधनों के बल पर खुदरा कारोबार को अपने नियंत्रण में कर लेती हैं।

स्वदेशी जागरण मंच के श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने अफसोस जताया कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी जोरदार लॉबिंग कई बड़े किसानों और दूसरे संगठनों को अपने हित मे बोलने के लिए राजी कर लिया है।

खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश किसानों, छोटे खुदरा कारोबारियों और देश तीनों के लिए समान रूप से खतरनाक है। इस नीति से यह सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान सरकार गरीबों के हितों के प्रति कितनी उदासीन है। उन्होंने कहा कि हम तकनीक और आधुनिकता के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम समाज के सबसे कमजोर वर्ग के अस्तित्व की रक्षा के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सम्मेलन दूसरे राज्यों में भी आयोजित होने चाहिए।

खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश किसानों, छोटे खुदरा कारोबारियों और देश – तीनों के लिए समान रूप से खतरनाक है। इस नीति से यह सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान सरकार गरीबों के हितों के प्रति कितनी उदासीन है। हम तकनीक और आधुनिकता के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम समाज के सबसे कमजोर वर्ग के अस्तित्व की रक्षा के प्रति संवेदनशील हैं।

– श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', स्वदेशी जागरण मंच

जानेमाने अर्थशास्त्री मोहन गुरूस्वामी ने सम्मेलन को सबोधित करते हुए कहा कि ये विदेशी निवेश के पूरी तरह से खिलाफ नहीं हैं लेकिन वैश्विक खुदरा व्यापारियों का कारोबारी मॉडल मोनोपॉलिस्ट बनाता है। अध्ययन से यह साबित हो जाता है कि बड़ी खुदरा कंपनियां थोक भाव से बड़े पैमाने पर खरीद करती हैं इससे खेत से जुड़े उत्पादों की कीमतें कम हो जाती हैं और वालमार्ट जैसी कंपनियां जहां भी गई हैं वहां से परंपरागत बाजार खत्म हो गए हैं और बड़ी कंपनियों का एकाधिकार हो गया है। एकाधिकारवादी खरीदार ही एकाधिकारवादी विक्रेता बन जाते हैं। वालमार्ट के कुल स्टॉक का 90 फीसदी चीन से आता है।

इसका सालाना टर्नओवर 422 अरब डॉलर का है और चीन से होने वाले आयात करीब 80 अरब डॉलर का है। इसलिए चीन से मंगाया जाने वाला हिस्सा उसके फायदे का बड़ा हिस्सा है। वालमार्ट अपने मोनोपॉलिस्ट ताकत से मजदूरी की दर को कम करता है। वह अपने सप्लायर पर दबाव बनाता है कि वे उत्पादों की कीमतें कम करें और जाहिर है कि इससे उत्पादक मजदूरों को कम मजदूरी देने के लिए मजबूर होते हैं।

जैसा कि चीन के बाजारों में देखने को मिल रहा है और यह जानकर तो और भी हैरानी होती है कि सरकार को इस बात की चिंता नहीं कि बेरोजगारों को नौकरी कैसे दे बल्कि वह वैश्विक खुदरा व्यापार में विदेश निवेश को लेकर ज्यादा चिंतित है। उन्होंने इस मुद्दे पर खुली बहस के लिए किसी बड़े मंच के नहीं होने पर भी दुख जताया।

अफसोसजनक बात तो यह है कि इस मुद्दे जुड़ा हर भागीदार अपने ही बारे में सोच रहे हैं उन्हें देश और किसानों की चिंता नहीं है। भारत में खराब भंडारण व्यवस्था का तर्क कमजोर है क्योंकि विकासशील देशों में अनाज की बर्बादी विकसित देशों की तुलना में कम है।

स्वदेशी जागरण मंच के श्री अश्विनी महाजन ने कहा कि सरकार ने खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का फैसला बिलकुल एकतरफा है। व्यापारी, किसान और खुदरा कारोबार से जुड़े बाकी लोग भी इस तरह के विदेशी निवेश के पूरी तरह से खिलाफ हैं। इसका समर्थन वही लोग कर रहे है जिनका इसमें अपना निहित स्वार्थ है। विकसित देशों के अध्ययन से यह साफ हो जाता है कि वैश्विक खुदरा कारोबार से किसानों का कभी भला नही हुआ है। अमरीका में खाने–पीने की चीजों का खुदरा कारोबार बढ़कर 1200 अरब डॉलर हो गया जबकि 2000 में यह

सरकार द्वारा खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का फैसला बिलकुल एकतरफा है। व्यापारी, किसान और खुदरा कारोबार से जुड़े बाकी लोग भी इस तरह के विदेशी निवेश के पूरी तरह से खिलाफ हैं। इसका समर्थन वही लोग कर रहे है जिनका इसमें अपना निहित स्वार्थ है। विकसित देशों के अध्ययन से यह साफ हो जाता है कि वैश्विक खुदरा कारोबार से किसानों का कभी भला नही हुआ है।

– डॉ. अश्विनी महाजन, स्वदेशी जागरण मंच

खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का मतलब सिर्फ यही है कि खानेपीने की चीजों के कारोबार का वैश्वीकरण। विदेशी खुदरा कारोबार भारत के छोटे खुदरा कारोबार के साथ कभी नहीं रह सकता है जो बड़े खुदरा कारोबारी हैं वे बड़ी सोच–समझ कर नीति बनाते हैं और ताकतवर लॉबिंग से सिस्टम को प्रभावित करते हैं।

– श्री शेखर स्वामी, विख्यात लेखक

आकड़ा महज 833 अरब डॉलर था। जबकि किसानों के खानेपीने की चीजों की बिक्री 25 फीसदी घट गई।

अमरीका के किसान भारत के किसानों से भी कम मुनाफा कमाते हैं। भारत में खाने–पीने की चीजों को जानबूझ कर बर्बाद किया जाता है कि ताकि इस बात पर जोर डाला जा सके इनके बेहतर रख–रखाव के लिए कोल्ड–स्टोरेज बनाने के लिए भारत में एफडीआई आवश्यक है। कोल्ड–स्टोरेज के लिए सरकार के पास 7800 करोड़ रुपये की कमी का बहाना काफी कमजोर है क्योंकि इतना पैसा तो घरेलू आमद में आराम से जुटाया जा सकता है।

किसान जागृति मंच (लखनऊ) के श्री सुधीर पनवर ने कहा कि बिना किसी बहस के ही इतना बड़ा फैसला ले लिया है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है। सभी अध्ययनों से यह साबित होता है कि खुदरा कारोबार से जब भी विदेशी निवेश को जोड़ा गया है तो इससे बेरोजगारी में इजाफा होता है। देश पूरी तरह से भंडारण सुविधाओं के विस्तार के लिए रकम जुटाने में समर्थ है लेकिन वर्तमान समय में जो अफरातफरी के हालात हैं उसके लिए सरकारी नीतियां और कुव्यवस्था ही जिम्मेदार है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों की मौजूदा हालत को सुधारा जाए और उनके लगातार गिरते सालाना आमदनी पर भी चिंता जाहिर की। उनके मुताबिक भारत में कारोबार सिर्फ कमाने का ही जरिया नहीं है बल्कि जिंदगी चलाने का माध्यम है।

मुंबई के विख्यात लेखक श्री शेखर स्वामी ने कहा कि खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का मतलब सिर्फ यही है कि खानेपीने की चीजों के कारोबार का वैश्वियकरण। विदेशी खुदरा कारोबार भारत के छोटे खुदरा कारोबार के साथ कभी नहीं रह सकता है जो बड़े खुदरा कारोबारी हैं वे बड़ी सोच–समझ कर नीति बनाते हैं और ताकतवर लॉबिंग से सिस्टम को प्रभावित करते हैं।

उन्होंने मैक्सिको का उदाहरण दिया जिसने 1994 में नॉर्थ अमरीका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था जिसके तहत मैक्सिको का बाजार पूरी तरह से खोल दिया गया लेकिन श्रम बाजार नहीं खुला जिससे मैक्सिको के खुदरा कारोबार पर कॉरपोरेट कब्जा हो गया जबकि 25 फीसदी से ज्यादा किसान खेती छोड़ने को मजबूर हुए। गैरकानूनी पलायन दोगुना हो चुका है और लोगों को विस्थापन बड़ा रूप ले चुका है।

उनके मुताबिक भारतीय बाजार काफी हद तक विकेंद्रित है और कोई एकाधिकार नहीं है लेकिन वैश्विक कारोबारियों के आने से हालात बदल जाएंगे और कीमतें भी बढ़ेंगी। भारत में फिलहाल लघु उद्योगों से ही 60 फीसदी सामान खरीदे जाते हैं जबकि विदेशी निवेश में यह 30 फीसदी ही है। इसका मतलब साफ है कि बाकी सामान विदेशी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश देश के हितों के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जानीमानी कृषि विशेषज्ञ वंदना शिवा ने कहा कि किसानों का मोहरा बनाकर सरकार इस नीति को लागू करना चाहती है जबकि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश आजादी और सच्चाई पर हमला है। बड़ी कंपनियां उत्पाद और आपूर्ति के सामान्य संबंधों का गला घोट देगीं। उन्होंने अफसोस जताया कि कोई भी विश्वसनीय किसान संगठन इस नीति का समर्थन नहीं किया है जबकि सरकार किसानों की आड़ में इस नीति को लागू करने की फिराक में है।

एक मजबूत खेती आधारित व्यवस्था खुदरा कारोबार की रीढ होती है। ये नीति किसानों को फायदा नहीं पहुचाने वाली है। जैसा कि मोनसेन्टो के मामले में देखा गया है जैसे ही इस कंपनी ने बीज कारोबार में कदम रखा तब से लेकर 2,50,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

किसानों को मोहरा बनाकर सरकार इस नीति को लागू करना चाहती है जबकि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश आजादी और सच्चाई पर हमला है। बड़ी कंपनियां उत्पाद और आपूर्ति के सामान्य संबंधों का गला घोट देगीं। उन्होंने अफसोस जताया कि कोई भी विश्वसनीय किसान संगठन इस नीति का समर्थन नहीं किया है जबकि सरकार किसानों की आड़ में इस नीति को लागू करने की फिराक में है।

– डॉ. वन्दना शिवा, कृषि विशेषज्ञ

यह तर्क कि बिचौलिए के नहीं होने से महंगाई में कमी आएगी–खुद में ही कमजोर तर्क है। क्योंकि बिचौलिए की जगह पर बड़े कारोबारी ले लेते हैं जिनका पेट बड़े मुनाफे से ही भरता है। हायपर मार्केट से गुणवत्ता, विविधता और स्वाद खत्म हो जाता है। स्वादिष्ट अनाज बर्बाद हो जाते हैं। बड़े कारोबारियों के उच्च–मानकीकरण से स्वाद और गुणवत्ता में कमी आती है। इसके बाद जीन–प्रसंस्कृत खादय सामग्री की खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है जो लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है।

भारत तो सनड्राई फूड–स्टोरेज के लिए जाना जाता था जहां कि रेफ्रीजरेशन की आवश्यकता न के बराबर है। रेफ्रीजरेशन जलवायु के लिए भी खतरनाक है। भारतीय औरतें फूड–स्टोरेज में माहिर हैं इसलिए हमें किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं है। बड़े कारोबारी हमारे संस्कृति और सभ्यता को भी प्रभावित करते हैं।

राजनीतिक सत्र

फॉरवर्ड ब्लॉक के सांसद श्री देवव्रत विश्वास ने इस लड़ाई में सबको एकजुटता की मांग करते हुए कहा कि समाजवादी और वाम धड़ा तो पूरी तरह खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश के खिलाफ एकजुट है। क्योंकि विदेशी निवेश एक तरह से विदेशी शासन की तरह है। हम अपने खेत, पानी और वातावरण पर से भी अधिकार खो देंगे। हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब लोकतांत्रिक सरकार की जगह कंपनी सरकार चल रही है जो सिर्फ कॉरपोरेट के मुनाफे के अलावा कुछ नहीं सोचती है। संसद को ताक पर रख दिया है। सरकार यह वकालत कर रही है कि राज्य इस नीति से खुद को अलग रखने को आजाद होंगे लेकिन वो यह बात भूल रही है कि भारत एक देश है। यह सच नहीं है कि बड़े आकार के खेत में ज्यादा उत्पादन होता है।

सच्चाई यह है कि छोटे आकार के खेत ही ज्यादा उपज देते हैं और ऐसे खेतों का हिस्सा 80 फीसदी है। उन्होंने सरकार से यह सवाल किया कि वह खुद क्यों नहीं आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए निवेश करती है जिसके लिए विकसित तकनीक की जरूरत नहीं है इसे स्वदेशी तकनीक से ही विकसित किया जा सकता है। उनके विचार से भारत में खेती के बेहतर विकास के लिए बेहतर बाजार और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने खुदरा कारोबारियों के बीच बेहतर नेटवर्क बनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि खुदरा कारोबार को परंपराओं से जोड़ने की आवश्यकता है।

अमूल के एमडी आर. एस. सोढ़ी ने माना कि विकसित देश में विदेशी किसान खुदरा कारोबार में मल्टीनेशनल के आने से नुकसान में ही रहे हैं। अगर किसी भी देश में फूड–चेन को नियंत्रित कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि पूरा देश पर कब्जा। भारत में अगर मल्टी–ब्रांड रीटेल की अनुमति दी जाती है तो यहां के डेयरी किसान भी वैसे ही संघर्ष करेंगे जैसा कि विदेशों में देखने का मिल रहा है। वैश्विक रीटेल चेन से भारतीय बाजार को जोड़ने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि भारतीय उपभोक्ता और किसान विदेशी उथल–पुथल से प्रभावित होने लगेंगे। अमरीका में डेयरी किसान की बिक्री 1996 में 52 प्रतिशत से घटकर 2009 में 38 प्रतिशत रह गई है। इसी तरह से यूके में 56 प्रतिशत से घटकर 38 प्रतिशत रह गया है।

विकसित देश में विदेशी किसान खुदरा कारोबार में मल्टीनेशनल के आने से नुकसान में ही रहे हैं। अगर किसी भी देश में फूड–चेन को नियंत्रित कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि पूरा देश पर कब्जा। भारत में अगर मल्टी–ब्रांड रीटेल की अनुमति दी जाती है तो यहां के डेयरी किसान भी वैसे ही संघर्ष करेंगे जैसा कि विदेशों में देखने का मिल रहा है।

– श्री आर.एस. सोढी, एमडी अमूल

जिस तरह से आज देश में वैश्विक साजिश हो रही है जिससे गरीबों का ही खात्मा हो जाए। सारी सरकारें अमरीकापरस्त होती जा रही हैं। खुदरा कारोबार में एफडीआई ऐसा ही मुद्दा है। हमें सरकार पर इस तरह की नीतियों के खिलाफ दबाव बनाना चाहिए।

– श्री संजय पासवान, पूर्व सांसद

उन्होंने यह भी कहा कि बिचौलिए के मुनाफे का आंकड़ा भी गलत और आधारहीन है। भारत छोटे कारोबारियों का देश है और इसे इसी तरीके से रहना चाहिए।

भारत कृषक समाज के प्रेसिडेंट डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने कहा कि अगर सरकार सचमुच किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है तो उसे अपनी नीतियों की दिशा बदल देनी चाहिए। हमें विदेशी अनुदान की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। देश में ही को–ऑपरेटिव के सफल उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे ही मॉडल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

अमेरिका आर्थिक संकट से जूझ रहा है जबकि भारत इस तरह के संकट से अब भी बचा हुआ है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे किसान और कारोबारी हैं। यह मॉडल हजारों साल से चला आ रहा है और कारगर है। वैश्विक कारोबारियों के लिए यह एग्री–बिजनेस है जबकि हमारे लिए यह परंपरा और संस्कृति है। खुदरा में विदेशी निवेश के खतरनाक अंजाम होंगे। – डॉ. मुरली मनोहर जोशी, भाजपा

जेनेटिकली मॉडिफायड फूड के जरिए कृत्रिम रंग, स्वाद और ग्रेड को जन्म दिया जाता है और इसमें किसानों का शोषण होता है।

पूर्व सांसद श्री संजय पासवान ने कहा कि इस तरह की वैश्विक साजिश हो रही है जिसमें गरीबों का ही खात्मा हो जाए। सारी सरकारें अमरीकापरस्त होती जा रही हैं। खुदरा कारोबार में एफडीआई ऐसा ही मुद्दा है। हमें सरकार पर इस तरह की नीतियों के खिलाफ दबाव बनाना चाहिए।

वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि खुदरा कारोबार में एफडीआई के खिलाफ संघर्ष में वे शामिल रहे हैं। अमेरिका आर्थिक संकट से जूझ रहा है जबकि भारत इस तरह के संकट से अब भी बचा हुआ है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे किसान और कारोबारी हैं। यह मॉडल हजारों साल से चला आ रहा है और कारगर है। वैश्विक कारोबारियों के लिए यह एग्री–बिजनेस है जबकि हमारे लिए यह परंपरा और संस्कृति है। खुदरा में विदेशी निवेश के खतरनाक अंजाम होंगे। यह देश के संसाधनों पर कब्जे की साजिश के अलावा कुछ नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत किसी तरह का शर्त नहीं रखा जा सकता है। इसलिए 30 फीसदी का कोटे की बात ही बेमानी है। इन विदेशी खुदरा कारोबारियों का विरोध तो विकसित देशों में भी हो रहा है। यह वालस्ट्रीट आंदोलन की शक्ल में निकल रहा है। उनकी नीति ही यही है सस्ता से सस्ता खरीद कर महंगा से महंगा बेचना। स्वतंत्र तरीके से खेती करना हमारी अर्थव्यवस्था की जान है इसलिए इसे हर हाल में बचाने की आवश्यकता है।

भागीदारी सत्र

नेशनल हॉकर्स असोसिएशन के महासचिव श्री शक्तिमान घोष ने कहा की इससे देश के हर सेक्टर को नुकसान होगा। हॉकर्स सबसे ज्यादा माल लघु–उद्योगों से खरीदते हैं। 80 फीसदी सब्जियां देश में हॉकर्स ही बेचते हैं। हॉकर 1000 कैलोरी सिर्फ 7 रूपये में प्रदान करता है। वैश्विक खिलाड़ियों के आने से कीमतों में इजाफा होगा और हॉकर्स और छोटे कारोबारी बुरी तरह प्रभावित होंगे हमें इनकी हितों की रक्षा के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है।

ग्रामीण स्वाभिमान के राजस्थान चैप्टर के प्रसिडेंट श्री भागीरथ चौधरी ने इसे गरीब भारत को और भी गरीब बनाने की साजिश करार दिया। सरकार जानबूझकर स्टेकहोल्डर्स के बीच भ्रम पैदा कर रही है और हमें इस मंशे को समझने की आवश्यकता है।

भारतीय मजदूर संघ के श्री पवन कुमार ने हमें विदेशों के अनुभवों से सीख लेने की आवश्यकता है जहां खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश के कुपरिणाम साफ दिख रहे हैं। विडंबना यह है कि जब भी विश्व व्यापार संगठन से समझौता होता है तो संसद को अंधेरे में रखा जाता है। उन्होंने खुदरा कारोबारियों और किसानों के हितों के लिए विदेशी निवेश के विरोध करने पर जोर दिया। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश की सरकारी नीतियों के खिलाफ 28 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया है और इसमें देश के कई बड़ी यूनियनें समर्थन करेंगी।

भारत उद्योग व्यापार मंडल के श्री बालकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि सरकार छोटे कारोबारी, किसान और उपभोक्ता के बीच कायम विश्वास के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। उसका सारा जोर कॉरपोरेट को समर्थन करने का है ताकि उनका मुनाफा बढ़े। जबकि सरकार को छोटे किसानों की मदद के लिए नीतियां बनानी चाहिए।

जर्मन कैथोलिक बिशप आर्गेनाईजेशन फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन मिसरर के श्री अरमीन पाश्च ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त कारोबार से काफी नकारात्मक असर पड़ रहा है। असंगठित क्षेत्र में 30 लाख से 60 लाख लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। हॉकर्स राईट टू फूड पर गंभीर असर पड़ेगा। असंगठित क्षेत्र का खुदा कारोबार में हिस्सा 90 फीसदी से घटकर 55 फीसदी रह जाएगा। मैक्सिको और अर्जेंटिना के अनुभव बताते हैं कि सुपर मार्केट सिर्फ महंगी खाने की चीजे बेचते हैं और इसका नकारात्मक असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

किसान महापंचायत के अध्यक्ष श्री रामपाल जाट ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। किसानों को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए किसानों ने 26 फरवरी जयपुर में रैली भी की है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंघल के मुताबिक यह तर्क कि एफडीआई से आधारभूत संरचना के विकास का दावा खोखला है। दरअसल सरकार की नीतियों में ही खामी है। इससे उत्पादों की कीमतें

किसान तो हमेशा से दुख झेलते आए हैं और व्यापारियों की भी अब यही स्थिति है। बिजली, तेल और परिवहन लागत बढ़ चुकी है लेकिन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करने को तैयार नहीं है। यही हालात रहे तो किसान भारत से विलुप्त हो जाएंगे।

– श्री नरेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन (उ.प्र.)

नहीं कम होने वाली है क्योंकि अभी तो किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस लड़ाई में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया।

नोएडा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राईजेज के श्री. पी.सी. कोसी के मुताबिक इस समस्या से विकसित और विकासशील देश दोनो ही बराबर प्रभावित हैं जो अब अरब देशों और बाकी देशों में भी दिख चुका है। उन्होंने सरकार से मांग कि है कि वह खुदरा व्यापार की आधिकारिक परिभाषा दें और एक व्यापक खुदरा व्यापार नीति देश के लिए बनाए। छोटे उद्योग और खुदरा कारोबार को उद्योग का दर्जा देने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया।

ग्राहक पंचायत के श्री ओ पी. सचदेव ने ब्रिटेन के आउटलुक मैगजीन का हवाला देते हुए कहा कि टेस्को खाने–पीने के खुदरा कारोबार पर 76 फीसदी कब्जा है। खेती लायक वातावरण होने के बाद भी आज ब्रिटेन अमेरिका और न्यूजीलैंड से खाद्यान्न आयात करने को मजदूर है। वैश्विक रीटेल कारोबारी आलू तो 5 रूपये प्रति किलो खरीदते हैं लेकिन चिप्स 100 रूपये किलो बेचते हैं।

भारतीय किसान संघ के महासचिव श्री प्रभाकर राव केलकर के मुताबिक विदेशी निवेश प्रतिस्पर्धा खत्म कर देगा और मध्यप्रदेश का आईटीसी का हरियाली बाजार इसका बेहतरीन उदाहरण है। हमें सभी एमएनसी और उनके उत्पादों का विरोध करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के श्री नरेश टिकैत के मुताबिक किसान तो हमेशा से दुख झेलते आए हैं और व्यापारियों की भी अब यही स्थिति है। बिजली, तेल और परिवहन लागत बढ़ चुकी है लेकिन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करने को तैयार नहीं है। यही हालात रहे तो किसान भारत से विलुप्त हो जाएंगे।

किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट श्री ओमप्रकाश धनखड़ के मुताबिक भारत की संप्रभुता के लिए फूड–सिक्योरिटी अहम है। सरकार की नीतियों के कारण किसान लगातार गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्यों खाद्य पदार्थों की कीमतें तय की जाती हैं और किसानों को कम पैसे दिए जाते हैं। उनके मुताबिक हर क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ लेकिन खेती को हमेशा नजरअंदाज किया गया। ऐसे में वैश्विक खुदरा कारोबारियो से भारत का भला नहीं होने वाला है।

सरकार काफी समय से रीटेल में विदेशी निवेश लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन घरेलू कारोबारी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक संप्रभुता बचाने के लिए आर्थिक संप्रभुता संरक्षित करना आवश्यक है। वायदा बाजार कॉरपोरेट के लिए तो अच्छा है लेकिन किसानों के लिए खतरनाक है।

– श्री मुरलीधर राव, महासचिव भाजपा

भाजपा के महासचिव श्री मुरलीधर राव ने कहा कि सरकार काफी समय से रीटेल में विदेशी निवेश लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन घरेलू कारोबारी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक संप्रभुता बचाने के लिए आर्थिक सप्रभुता संरक्षित करना आवश्यक है। वायदा बाजार कॉरपोरेट के लिए तो अच्छा है लेकिन किसानों के लिए खतरनाक है। वैश्विक खुदरा कारोबारियों के आने से महंगाई कम होगी ऐसा कहना हास्यास्पद है। उन्होंने मिलजुलकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया।

सीएआईटी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री बी. सी. भारतीय ने सम्मेलन के समापन सत्र में सबकी ओर से कहा कि एफडीआई ज्वलंत मुद्दा है जिसका जीताजागता सबूत है कि इतने सारे स्टेकहोल्डर्स एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं।

उन्होंने सभी भागीदारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संयुक्त समिति बनाने की घोषणा की। इस तरह के राज्य–स्तरीय सम्मेलन सभी राज्यों में आयोजित होंगे और संयुक्त समिति के प्रतिनिधि अलग–अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अलग–अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर ज्ञापन देंगे। संयुक्त समिति बहुत जल्द इस बात का फैसला करेगी कि भविष्य में किस तरह की रणनीति अपनानी है।

– प्रस्तुति प्रवीन खंडेलवाल

वित्तीय घाटे पर नियंत्रण के उपाय

मनमोहन सिंह सरकार ने अनायास ही अर्थव्यवस्था को गड्ढे मे ढकेल दिया है। टैक्स पालिसी को जन–कल्याण का अस्त्र बनाने के स्थान पर केवल आय बढ़ाने का साधन बना दिया है। इस आय का रिसाव हो रहा है। अतः वित्तीय घाटे पर नियंत्रण का सीधा रास्ता भ्रष्टाचार पर सख्ती एंव आर्थिक पालिसियों को जन–कल्याण की तरफ मोड़ना है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने स्वीकार किया है कि सरकार का वित्तीय घाटा पूर्वानुमान से बहुत अधिक होगा। पहला कारण है कि इस वर्ष सरकार को विनिवेश से पर्याप्त रकम नहीं मिली है। पिछले वर्ष स्पेक्ट्रम की बिक्री से लगभग 100 हजार करोड़ रूपये मिले थे जिससे घाटा कम हो गया था। खर्च पिछले वर्ष भी बढ़े थे परन्तु ये दिखाई नहीं पड़े चूंकि आय भी बढ़ गई थी। परन्तु स्पेक्ट्रम की बिक्री जैसी आय कई दशकों में एक बार होती है। इस वर्ष ऐसी आय न होने के कारण बढ़े हुए खर्च दिखने लगे हैं। इन्हें पोषित करने के लिए सरकार को ऋण लेने पड़े हैं और वित्तीय घाटा बढ़ रहा है।

वित्तीय घाटे के बढ़ने का दूसरा कारण सब्सिडी मे वृद्धि है। सरकार ने पेट्रोल के दाम वैश्विक दाम से जोड़ दिये हैं परन्तु डीजल पर सब्सिडी जारी है जिससे यह भार बढ़ रहा है। खाद्यान्न सब्सिडी तथा रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर भी खर्च बढ़ रहा है।

तीसरा कारण बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। सरकारी राजस्व का उपयोग सड़क आदि बनाने के लिए किया जाए तो दोहरा लाभ होता है। श्रम एवं सीमेंट आदि की मांग पैदा होती है। साथ–साथ अच्छी सड़क उपलब्ध होने से ढुलाई का खर्च कम पड़ता है। उसी राजस्व को स्विस बैंक मे जमा करा दिया जाए तो देश की क्रयशक्ति कम होती जाती है। देश मे मंदी आती है जिससे तोड़ने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाया जाता है और वित्तीय घाटा बढ़ता है।

वित्तीय घाटे का सिद्धांत है कि किन्ही कठिन परिस्तिथियों मे अर्थव्यवस्था को झटका लगे तो उससे उबारने के लिए कुछ समय के लिए सरकारी खर्च बढ़ा दिए जाए। वाइरल फीवर से पीड़ित व्यक्ति को कुछ समय के लिए टोनिक दे दिया जाए तो वह पुनः काम पर जाने को खड़ा हो

वित्तीय घाटे के बढ़ने का दूसरा कारण सब्सिडी मे वृद्धि है। सरकार ने पेट्रोल के दाम वैश्विक दाम से जोड़ दिये हैं परन्तु डीजल पर सब्सिडी जारी है जिससे यह भार बढ़ रहा है। खाद्यान्न सब्सिडी तथा रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर भी खर्च बढ़ रहा है। तीसरा कारण बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। सरकारी राजस्व का उपयोग सड़क आदि बनाने के लिए किया जाए तो दोहरा लाभ होता है। श्रम एवं सीमेंट आदि की मांग पैदा होती है। साथ–साथ अच्छी सड़क उपलब्ध होने से ढुलाई का खर्च कम पड़ता है।

जाता है अथवा गर्मी से मुरझाते पौधे को पानी दे दिया जाए तो उसकी कलियाँ फूलने लगती है। इसी प्रकार मंदी से पीड़ित भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए वित्तीय घाटे का सहारा देने से अर्थव्यवस्था चल निकलेगी ऐसी मान्यता है। यह सोच सही है।

परन्तु सोचिये कि वाइरल फीवर से पीड़ित व्यक्ति को टॉनिक के नाम पर शिकंजी पिला दी जाए और कम्पाउन्डर द्वारा टानिक को नं 2 में दुकानदार को बेच दिया जाए तो क्या होगा? मरीज के परिवार को टॉनिक का पैसा देना होगा जब कि उसे लाभ मिलेगा केवल शिकंजी का। जो च्यवनप्राश वह बाजार से खरीद कर रोगी को खिला सकता था वह भी नही हो सकेगा और रोग बढ़ जाएगा। अथवा यदि सूखे से मुर्झाते पौधों को पिलाने के नाम पर टैंकर से पानी मंगवाया जाए परन्तु पौधे को एक लोटा जल डाल कर शेष को नहाने का उपयोग कर लिया जाए तो क्या होगा? पौधा संभवतः जीवित रहेगा परन्तु कलियाँ फूलेंगी नहीं।

किसान की बिजली के बिल को अदा करने की क्षमता जाती रहेगी चूँकि उसने टैंकर मंगवाने में धन खर्च कर दिया है। अंततः उसकी खेती चौपट हो जाएगी। तात्पर्य यह कि वित्तीय घाटे के तहत सरकारी खर्च की सार्थकता तब ही है जब इन खर्च को बिना रिसाव के लागू किया जाए।

कुछ वर्ष पूर्व भारत के कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल श्री वी. के. शुंगलू ने एक गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा था कि वित्तीय घाटे का कारण टैक्स वसूली मे गडबड़ी एवं सरकारी खर्चों की गिरती गुणवत्ता है। श्री शुंगलू ने बताया था कि सरकार के खर्चों मे रिसाव होने के कारण सरकार की आय मे वृद्धि नही हो रही है। इसलिए सरकार को उत्तरोत्तर अधिक ऋण लेने पड़ रहे हैं और वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। यदि सरकारी खर्चों मे रिसाव न होता तो निवेश की गई रकम से अर्थव्यवस्था मे उत्पादन बढ़ता, सरकार को टैक्स अधिक मिलता और लिए गए ऋण की अदायगी हो जाती।

वित्तीय घाटे का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि सरकारी खर्चो मे भारी रिसाव हो रहा है। जैसे मरीज को लगातार टॉनिक पिलाने की जरूरत पड़ना इस बात का प्रमाण है कि टॉनिक का रिसाव हो रहा है अथवा पौधे को देने को लगातार टैंकर से पानी मंगवाना इस बात का प्रमाण है कि टैंकर के पानी का रिसाव हो रहा है।

सरकार ने भ्रम फैला रखा है की वित्तीय घाटे के बढ़ने का कारण वैश्विक मंदी है। यह स्पष्टीकरण मान्य नही है। इतना सही है कि वैश्विक मंदी के कारण हमारे निर्यात दबाव मे हैं। परन्तु निर्यात में आई कमी की भरपाई रूपये के अवमूल्यन के कारण मिली अधिक रकम से हो गई है।

मंदी का एक और कारण विदेशी पूंजी के आगमन में कमी बताया जा रहा है। सही है कि वैश्विक मंदी के कारण विदेशी पूंजी का बहाव हमारी तरफ कम हुआ है। परन्तु इसका कारण भी सरकारी खर्चो की गिरती गुणवत्ता है। यूरोप के संकट में आने से यूरोपीय देशों से पूंजी का पलायन हुआ है।

मुझे आशा थी कि यह पूंजी भारत की ओर मुड़ेगी। अमरीका की हालत अंदर से खराब ही है। अतः विश्व के निवेशकों को सुरक्षित स्थान की खोज थी जो कि भारत उपलब्ध करा सकता था। परन्तु हमने यह सुअवसर गँवा दिया है। सरकारी खर्चों की गुणवत्ता में गिरावट तथा भ्रष्टाचार के कारण वित्तीय घाटे के बढ़ने से निवेशकों का भारत पर भरोसा उठ गया है।

राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर किये जा रहे खर्च को जोड़ लें तो मेरे अनुमान मे सब्सिडी पर कुल खर्च लगभग 7,000 करोड़ रूपये प्रति वर्ष होगा। यह विशाल खर्च मुख्यतः अनुत्पादक है एंव सरकारी कर्मियों की खपत को पोस रहा है। जन–कल्याण की पालिसी को खर्च के स्थान पर आय का माध्यम बनाया जा सकता है। सरकार द्वारा एक्साइज डयूटी तथा इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है। इस टैक्स का भार सभी उद्योगों पर बराबर पड़ता है। करना चाहिए कि इस टैक्स को उन विशेष उद्योगों से अधिक मात्रा मे वसूल किया जाए जहाँ रोजगार का भक्षण होता है। हार्वेस्टर, एक्सकावेटर, बोतलबंद शीतल पेय, पावर लूम इत्यादि पर अधिक टैक्स लगा दिया जाए तो खेत मजदूर, रसवती एवं हथकरघे जैसे उद्योग स्वयं चल पड़ेंगे। गरीब को रोजगार स्वतः ही मिल पाएगा और कल्याणकारी खर्चों की आवश्यकता कम हो जाएगी। दूसरे श्रम–सघन उद्योगों पर टैक्स की दर घटा देनी चाहिए जैसे अगरबत्ती, फूड प्रोसेसिंग इत्यादि पर। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था पर टैक्स का कुल भार भी नही बढ़ेगा।

मनमोहन सिंह सरकार ने अनायास ही अर्थव्यवस्था को गड्ढे मे ढकेल दिया है। टैक्स पालिसी को जन–कल्याण का अस्त्र बनाने के स्थान पर केवल आय बढ़ाने का साधन बना दिया है। इस आय का रिसाव हो रहा है। अतः वित्तीय घाटे पर नियंत्रण का सीधा रास्ता भ्रष्टाचार पर सख्ती एवं आर्थिक पालिसियों को जन–कल्याण की तरफ मोड़ना है। ❑

सरकारी कर्ज के भंवर से बचे भारत

हाल ही में रिजर्व बैंक के गर्वनर ने चेतावनी दी है कि यदि राजकोषीय घाटे को रोकने के कारगर कदम नहीं उठाये गये तो भारत भी कर्ज के भंवर में फंस सकता है। भारत में केन्द्रीय सरकार का कर्ज अब जीडीपी के 65 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हमारा कर्ज–जीडीपी अनुपात हंगरी के बाद सबसे अधिक है। वर्ष 2011–12 में बजट अनुमानों के अनुसार केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 4.13 लाख करोड़ रूपये था। कहा जा रहा है कि वास्तव में यह घाटा इससे कहीं अधिक रहेगा.

■ डॉ. अश्विनी महाजन

अभी हाल ही में ग्रीस समेत यूरोपीय समुदाय के कई देश बढ़ते सरकारी कर्ज के चलते अपनी संप्रभुता को खोने का दंश सह रहे हैं। हाल ही में ग्रीस की संसद द्वारा यूरोपीय समुदाय के 130 अरब यूरो के सहायता पैकेज की शर्त के अनुसार कटौती प्रस्तावों को पारित किया है।

ग्रीस की जनता के भारी विरोध के बावजूद, ग्रीस को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उठाया गया यह कदम वर्तमान परिस्थितियों में सही ठहराया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से ग्रीस को कटौती के लिए बाहरी ताकतों द्वारा मजबूत किया जा रहा है, वह ग्रीस के संप्रभुता के खतरे की ओर सीधा इशारा कर रहा है। इसी प्रकार से इटली, पुर्तगाल सहित कुछ अन्य देश भी इसी प्रकार के संप्रभुता के संकट से जूझ रहे हैं।

सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर संप्रभुता के संकट के कारण क्या है? ग्रीस, इटली, पुर्तगाल और जर्मनी सरीखे यूरोपीय देशों में सरकारों के बढ़ते खर्च और उसके कारण लिए जा रहे कर्ज के कारण सरकार को कर्ज वापसी में होने वाली कठिनाई और संभावित कोताही ने इन देशों के लिए संप्रभुता का संकट खड़ा कर दिया है।

मात्र 130 अरब यूरो के सहायता पैकेज के लिए ग्रीस की सरकार को यूरोपीय समुदाय की शर्तों के अनुसार अपनी आर्थिक नीतियां बदलनी पड़ रही हैं। अत्यंत जरूरी सामाजिक सुरक्षा संबंधी खर्चों में भी कटौती की जा रही है। कमोवेश इस प्रकार के संकट से जूझ रहे अन्य यूरोपीय देशों में भी संप्रभुता के संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

ग्रीस की जनता के भारी विरोध के बावजूद, ग्रीस को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उठाया गया यह कदम वर्तमान परिस्थितियों में सही ठहराया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से ग्रीस को कटौती के लिए बाहरी ताकतों द्वारा मजबूत किया जा रहा है, वह ग्रीस के संप्रभुता के खतरे की ओर सीधा इशारा कर रहा है। इसी प्रकार से इटली, पुर्तगाल सहित कुछ अन्य देश भी इसी प्रकार के संप्रभुता के संकट से जूझ रहे हैं।

कर्ज के भंवर में फंसता भारत

हाल ही में रिजर्व बैंक के गर्वनर ने चेतावनी दी है कि यदि राजकोषीय घाटे को रोकने के कारगर कदम नहीं उठाये गये तो भारत भी कर्ज के भंवर में फंस सकता है। भारत में केन्द्रीय सरकार का कर्ज अब जीडीपी के 65 प्रतिशत तक

पहुंच चुका है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हमारा कर्ज–जीडीपी अनुपात हंगरी के बाद सबसे अधिक है। वर्ष 2011–12 में बजट अनुमानों के अनुसार केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 4.13 लाख करोड़ रूपये था।

कहा जा रहा है कि वास्तव में यह घाटा इससे कहीं अधिक रहेगा। इस घाटे की आंशिक रूप से पूर्ति रिजर्व बैंक से उधार लेते हुए नये नोट छाप कर की जायेगी, लेकिन इस घाटे की अधिकतम भरपाई पूर्व के अनुसार अतिरिक्त ऋण जुटाकर ही की जायेगी। केन्द्र सरकार पर कुल कर्ज 2002–03 में मात्र 15.59 लाख करोड़ से बढ़ते हुए 2011–12 तक 43.53 लाख करोड़ रूपये हो चुका है। इसके अतिरिक्त 18.2 लाख करोड़ रूपये का कर्ज राज्य सरकारों पर है।

वर्ष 2011–12 के बजट में केन्द्र सरकार को मात्र ब्याज की अदायगी में 2.68 लाख करोड़ रूपये खर्च करने पड़े। यदि केन्द्र सरकार का कर्ज इसी प्रकार से बढ़ता गया तो हर बार टैक्सों से होने वाली प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा ब्याज की अदायगी में ही चला जायेगा। ऐसे में सरकार के पास शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सामाजिक सेवाओं पर खर्च करने के लिए धन नहीं बचेगा और हर बार इन खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार को और ज्यादा ऋण लेने पड़ेंगे।

सरकार द्वारा कृषि की अनदेखी के चलते किसानों की घटती आमदनियां और उन पर बढ़ता कर्ज का बोझ सरकार को कर्ज माफी की योजना लाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये ऐसे गैर जरूरी सरकारी खर्च हैं जिनसे रोजगार प्रधान और कृषि विकास की आर्थिक नीतियों के माध्यम से बचा जा सकता है।

अपने ही संकल्पों को पूरा नहीं कर पाई सरकार

कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने एफ.आर.बी.एम. कानून पास करते हुए स्वयं पर यह अंकुश लगाया था कि राजकोषीय घाटे को कम करते हुए उसे तीन वर्षों में 2.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा, लेकिन सरकार अपने इस संकल्प पर अडिग न रह सकी और अपने ही संकल्प की धज्जियां उड़ाते हुए वर्ष 2008–09 में राजकोषीय घाटे को लगभग 7 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया।

सरकार ने इसके लिए यह तर्क दिया कि वैश्विक मंदी से उबरने के लिए सरकार को एक ओर करों में छूट देनी पड़ी और दूसरी ओर सरकारी व्यय बढ़ाना पड़ा। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अनुरूप अपने राजकोषीय घाटे को कम करके उसे 2.5 प्रतिशत पर लाने के लिए संकल्पित है। लेकिन वर्ष 2011–12 में भी राजकोषीय घाटा जीडीपी का लगभग 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यदि राज्य सरकारों का

बढ़ते विदेशी कर्ज और खासतौर पर लघुकालीन विदेशी कर्ज का मुख्य कारण हमारा बढ़ता व्यापार घाटा है। लगातार बढ़ते व्यापार घाटे के कारण हमारी सेवाओं के बड़े निर्यात और प्रवासी भारत द्वारा भेजे जा रहे अपार धन के बावजूद हमारा भुगतान शेष का घाटा लगातार बढ़ता हुआ वर्ष 2010–11 में 130.5 अरब डालर तक पहुंच गया है।

राजकोषीय घाटा भी इसमें जोड़ दिया जाए तो कुल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 10 प्रतिशत हो जाता है। स्वभाविक है कि बड़े राजकोषीय घाटे देश को कर्ज के बड़े भंवर की ओर धकेल रहे हैं।

पिछले वर्षों में सरकारों की लोकलुभावन नीतियों के चलते सरकारी बजट में अनुशासनहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली भूमंडलीकरण की नीतियों के कारण पूंजी प्रधान तकनीकों का उपयोग तो बढ़ा ही है, विदेशों से बढ़ते आयातों के कारण देश में लघु और कुटीर उद्योगों में रोजगार के अवसर भी कम हुए हैं।

विदेशी कर्ज और उभरते खतरे

देश पर विदेशी कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2005 में विदेशी कर्ज जो मात्र 134 अरब डालर ही था, वह बढता हुआ 2011 में 306 अरब डालर तक पहुंच गया। हाल ही के वर्षों में न केवल विदेशी कर्ज में भारी वृद्धि हुई है, बल्कि कुल विदेशी कर्ज में लघुकालीन विदेशी कर्ज 2006–07 में 20 प्रतिशत से बढता हुआ हाल ही में 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके चलते हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो मात्र 293 अरब डालर का है, उसका अधिकांश हिस्सा इस लघुकालीन विदेशी कर्ज को चुकाने में ही खर्च हो सकता है।

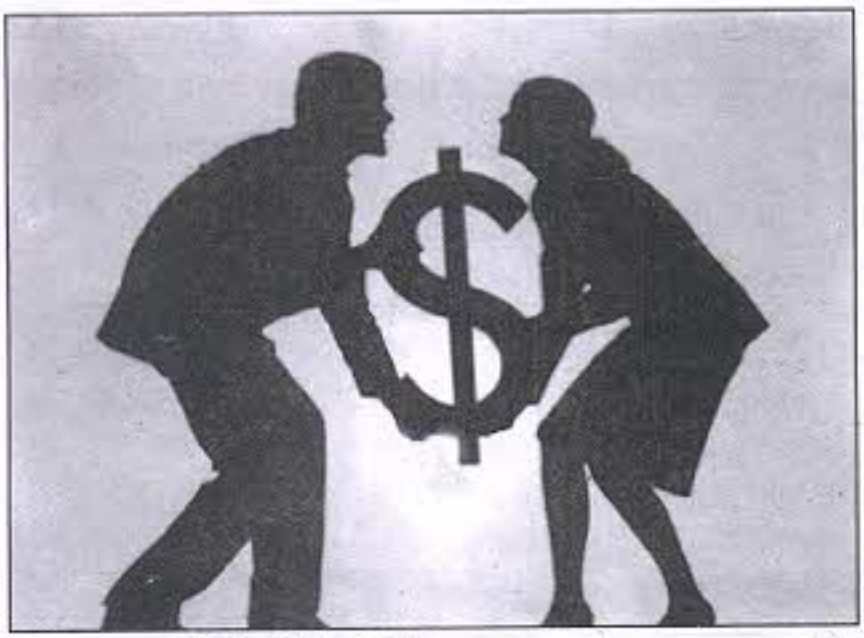

ऐसे में अन्य मुद्राओं की तुलना में रूपया और भी ज्यादा कमजोर हो सकता है। बढते विदेशी कर्ज और खासतौर पर लघुकालीन विदेशी कर्ज का मुख्य कारण हमारा बढ़ता व्यापार घाटा है। लगातार बढ़ते व्यापार घाटे के कारण हमारी सेवाओं के बड़े निर्यात और प्रवासी भारत द्वारा भेजे जा रहे अपार धन के बावजूद हमारा भुगतान शेष का घाटा लगातार बढ़ता हुआ वर्ष 2010–11 में 130.5 अरब डालर तक पहुंच गया है। भुगतान शेष का यह घाटा देश पर विदेशी कर्ज बढाने का बड़ा सबब बन रहा है।

आर्थिक नीतियों में जरूरी हैं बड़े बदलाव

पिछले वर्षों में सरकारों की लोकलुभावन नीतियों के चलते सरकारी बजट में अनुशासनहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली भूमंडलीकरण की नीतियों के कारण पूंजी प्रधान तकनीकों का उपयोग तो बढ़ा ही है, विदेशों से बढ़ते आयातों के कारण देश में लघु और कुटीर उद्योगों में रोजगार के अवसर भी कम हुए हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित 66वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार देश में स्वरोजगार 2004–05 और 2009–10 के बीच 251 लाख घटा और उसके स्थान पर आकस्मिक रोजगार 220 लाख बढ़ा।

ऐसे में घटते रोजगार के अवसर सरकार को नरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजनाएं चलाने के लिए बाध्य करती है, जिन पर हर वर्ष 40 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक का खर्च आता है। सरकार द्वारा कृषि की अनदेखी के चलते किसानों की घटती आमदनियां और उन पर बढ़ता कर्ज का बोझ सरकार को कर्ज माफी की योजना लाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये ऐसे गैर जरूरी सरकारी खर्च हैं जिनसे रोजगार प्रधान और कृषि विकास की आर्थिक नीतियों के माध्यम से बचा जा सकता है। साथ ही साथ सरकारों को फिजूल खर्ची से बचते हुए अपने खर्चों पर अंकुष लगाना होगा। नीतियों के सही मिश्रण से ही कर्ज के इस भंवर से बचा जा सकता है। ❑

तेल के लिए खेल

पूंजीवादी पैसे और सत्ता को अपना ईश्वर बना लेता है और फिर उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए लगभग सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसने सारी संस्कृतियों और धर्मों को गंभीर हानि पहुंचाई है और अब वह अपना ही विनाश कर रहा है। प्रतिस्पर्धा मानव प्राणियों के बीच का आवश्यक और सबसे मजबूत संबंध है। बाजार चाहे जिस सीमा तक बढ़ाए जा सकते हैं। अंत में पैसा ही सब मूल्यों का उचित माप है और राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता का संचालन सर्वोच्च मानव प्रवृत्ति पर है। अनियंत्रित पूंजीवाद पर अब और विश्वास नहीं किया जा सकता।

■ निरंकार सिंह

पूरी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जंग जारी है। यह जंग व्यापार के कुटिल नियमों से लेकर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से लड़ी जा रही है। जब इससे काम नहीं बनता है तो सीधे हमला कर दिया जाता है। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया से लेकर ईरान तक जंग का कारण कच्चा तेल है। अब ईरान की बारी है।

ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव का कारण कच्चे तेल का संकट ही है। हालांकि घोषित तौर पर इसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम बताया जा रहा है। ईरान ने फरवरी माह में यह घोषणा कर दी थी कि वह संघ के देशों और ब्रिटेन को तेल का निर्यात बंद कर देगा। इसके बाद से ही यूरोपीय संघ और ईरान के बीच तनाव गहरा गया।

ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम का प्रदर्शन करके इस संकट को और बढ़ा दिया है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन को लगता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए कार्यक्रम चला रहा है। पर संघर्ष और तनाव का असली कारण तेल का संकट ही है। पश्चिमी देश कोयला, पेट्रोल और सब प्रकार के खनिज पदार्थ अपार मात्रा में खर्च कर रहे हैं।

ग्रेट ब्रिटेन की बची हुई कोयले की खानें अब इतनी ज्यादा गहरी, ढालू तथा तंग हैं कि वहां कोयला निकालना दिनोंदिन अधिक कठिन और खर्चीला होता जा रहा है। अब उसे ईंधन के लिए मुख्यतः मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर रहना पड़ता है। उसे अपने उद्योगों के लिए लगभग सारा ही कच्चा माल बाहर से मंगाना पड़ता है।

अमेरिका ने 1900 की अपेक्षा 2010 में जलने वाला कोयला दस गुना, तांबा पांच गुना, जस्ता चार गुना और बिना साफ किया हुआ तेल (क्रूड ऑयल) तीस गुना अधिक जमीन से निकाला। राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा नियुक्त सामग्री-नीति आयोग की 1952 की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश धातुओं की और खनिज साधनों की जो मात्रा पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका

अमेरिका के पास संसार की गैर साम्यवादी जनसंख्या का 10 प्रतिशत से कम हिस्सा है और गैर साम्यवादी क्षेत्रफल का केवल 8 प्रतिशत हिस्सा है, परंतु 2010 में वह पेट्रोल, रबर, कच्चा लोहा, मैंगनीज और जस्ता जैसे बुनियादी कच्चे माल की समूचे संसार की उत्पन्न मात्रा का आधे से ज्यादा खर्च करता था। 2030 तक अमेरिका की कच्चे माल की मांग संभवतः कई गुना बढ़ जाएगी।

पूंजीवादी व्यवस्था पर अंकुश लगाया जा रहा है, क्योंकि सिद्धांत के रूप में पूंजीवाद आत्मघातक है। इस युग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रहे हैं महात्मा गांधी। गांधीजी ने आर्थिक प्रश्नों पर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने जिस आर्थिक सिद्धांत का विवेचन किया है वह हिंदू समाज से और संभवतः बौद्ध समाज से भी मेल खाता है। कोई भी व्यक्ति या समाज जब तक अपनी संपत्ति का उपभोग अपने साथियों के साथ करने को तैयार नहीं होगा तब तक वह अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। नहीं तो लोग विद्रोह करेंगे और एक–दूसरे के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। स्वेच्छा से सांसारिक सुखों का त्याग लोकतंत्र के लिए नितांत आवश्यक है।

ने उपयोग किया, वह 1914 से पहले पूरी दुनिया के उपभोग से ज्यादा था। अमेरिका की जनसंख्या पिछले 50 वर्ष में दोगुनी हो गई है। वहां सारे खनिज पदार्थों का उत्पादन आठ गुना तक बढ़ा और विद्युत शक्ति का उपयोग बीस गुना ज्यादा है। 1900 में अमेरिका ने अपने उपभोग से लगभग 15 प्रतिशत अधिक उत्पादन किया जबकि 2010 में वह अपने उत्पादन से 50 प्रतिशत अधिक सामग्री खर्च कर रहा था।

इस देश की कंपनियां और शेयर बाजार कभी अपने उपभोक्ताओं के खर्च का आंकड़ा देखकर नाच उठती थीं, लेकिन आज वे गहरे संकट में है। अमेरिका के पास संसार की गैर साम्यवादी जनसंख्या का 10 प्रतिशत से कम हिस्सा है और गैर साम्यवादी क्षेत्रफल का केवल 8 प्रतिशत हिस्सा है, परंतु 2010 में वह पेट्रोल, रबर, कच्चा लोहा, मैंगनीज और जस्ता जैसे बुनियादी कच्चे माल की समूचे संसार की उत्पन्न मात्रा का आधे से ज्यादा खर्च करता था। 2030 तक अमेरिका की कच्चे माल की मांग संभवतः कई गुना बढ़ जाएगी। इसमें खनिज पदार्थों से लेकर धातुएं, ईंधन और अन्य पदार्थ शामिल हैं।

खेती और उद्योगों के लिए पानी की आवश्यकता लगभग 200 प्रतिशत अधिक होगी। इस अवधि में अमेरिका की जनसंख्या जितनी बढ़ने की आशा है, उससे यह बढ़ोतरी बहुत अधिक है। वर्ष 2000 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने कच्चे माल के निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक किया है और यह घाटा बढ़ता जा रहा है। मंदी से पहले 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिन महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों का आयात किया था उनमें कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा लोहा, मैग्नीशियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता, सीसा, बॉक्साइट, पारा, ग्रेफाइट, एंटिमनी, कोबाल्ट, मैंगनीज के अलावा एसबेस्टस, गिलट, टीन, क्रोमाइट तथा औद्योगिक उपयोग के लिए हीरे शामिल थे।

इन आंकड़ों से दुनिया के सबसे ज्यादा उद्योग प्रधान राष्ट्र में कच्चे माल की अदम्य भूख और उसके अविचारपूर्ण खर्च तथा पूंजीवाद की इस विशेष प्रवृत्ति का ही प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि यह भी सिद्ध होता है कि पूंजीवाद में मर्यादा का कोई सिद्धांत नहीं होता। निरंतर बढ़ते रहने वाले बाजार का सिद्धांत पूंजीवाद का मूलभूत सिद्धांत है। पूंजीवादी उद्योगवाद प्राकृतिक साधनों को इतनी तेजी से खर्च कर रहा है कि कहा जा सकता है कि वह

आंकड़ों से दुनिया के सबसे ज्यादा उद्योग प्रधान राष्ट्र में कच्चे माल की अदम्य भूख और उसके अविचारपूर्ण खर्च तथा पूंजीवाद की इस विशेष प्रवृत्ति का ही प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि यह भी सिद्ध होता है कि पूंजीवाद में मर्यादा का कोई सिद्धांत नहीं होता। निरंतर बढ़ते रहने वाले बाजार का सिद्धांत पूंजीवाद का मूलभूत सिद्धांत है। पूंजीवादी उद्योगवाद प्राकृतिक साधनों को इनती तेजी से खर्च कर रहा है कि कहा जा सकता है कि वह हमारी भावी संतानों, कमजोर राष्ट्रों और जातियों की संपत्ति पर मौज उड़ा रहा है और अच्छे जीवन की सामग्री से उन्हें वंचित कर रहा है।

हमारी भावी संतानों, कमजोर राष्ट्रों और जातियों की संपति पर मौज उड़ा रहा है और अच्छे जीवन की सामग्री से उन्हें वंचित कर रहा है।

पूंजीवादी देशों को अब घटते उत्पादन के नियम का सामना करना पड़ रहा है? ये सफलताएं बड़ी हद तक इस कारण मिलीं कि अमेरिका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे प्रदेशों के द्वार इनके लिए खुले रहे। यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन ने एशिया और अफ्रीका का शोषण किया और विज्ञान तथा शिल्प विज्ञान की उन्नति हुई। अब कोई खाली उपजाऊ प्रदेश नहीं रह गया है।

यूरोप और ब्रिटेन के बाहर उद्योगों का विकास न होने और युद्धों के कारण राजनीतिक परिवर्तन होने तथा गरीबी फैलने से सब जगह बाजार संकुचित होते गए। यूरोप और इंग्लैंड के सिवाय सब जगह भूमि क्षरण के कारण अन्न उत्पादन लगातार घट रहा है। सत्ता थोड़े से लोगों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। विभिन्न दलों में विरोध बढ़ रहा है और सत्ता का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

युद्ध बार-बार होते हैं उनकी व्यापकता बढ़ती है और वे अधिकाधिक विनाशकारी होते जाते हैं। शोषण सिर्फ लोगों के ही खिलाफ काम नहीं करता, बल्कि भूमि और जंगलों के विरुद्ध भी काम करता है। पूंजीवादी पैसे और सत्ता को अपना ईश्वर बना लेता है और फिर उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए लगभग सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसने सारी संस्कृतियों और धर्मों को गंभीर हानि पहुंचाई है और अब वह अपना ही विनाश कर रहा है। प्रतिस्पर्धा मानव प्राणियों के बीच का आवश्यक और सबसे मजबूत संबंध है। बाजार चाहे जिस सीमा तक बढ़ाए जा सकते हैं। अंत में पैसा ही सब मूल्यों का उचित माप है और राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता का संचालन सर्वोच्च मानव प्रवृत्ति पर है। अनियंत्रित पूंजीवाद पर अब और विश्वास नहीं किया जा सकता। यह अब असह्य हो गया है।

अपनी प्रारंभिक अवस्था में शायद इसने मानव जाति के लिए अनेक कीमती काम किए। जिस विज्ञान और शिल्प विज्ञान का उसने प्रयोग किया वे मानव जाति के लिए मूल्यवान हैं, परंतु अब हर जगह पूंजीवादी व्यवस्था पर अंकुश लगाया जा रहा है, क्योंकि सिद्धांत के रूप में पूंजीवाद आत्मघातक है। इस युग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रहे हैं महात्मा गांधी। गांधीजी ने आर्थिक प्रश्नों पर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने जिस आर्थिक सिद्धांत का विवेचन किया है वह हिंदू समाज से और संभवतः बौद्ध समाज से भी मेल खाता है। कोई भी व्यक्ति या समाज जब तक अपनी संपत्ति का उपभोग अपने साथियों के साथ करने को तैयार नहीं होगा तब तक वह अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। नहीं तो लोग विद्रोह करेंगे और एक-दूसरे के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। स्वेच्छा से सांसारिक सुखों का त्याग लोकतंत्र के लिए नितांत आवश्यक है। ❑

हमें एहसास नहीं है कि स्वराज की लगभग पूर्ण प्राप्ति स्वदेशी से ही हो सकती है। यदि हम अपनी देशी भाषा के प्रति आदरभाव नहीं रखते हैं, यदि हम अपने वस्त्रों को नापसंद करते हैं, यदि हमारे पहनावे से हमें घृणा है, यदि हम पवित्र शिखा धारण करने में शर्म अनुभव करते हैं, यदि हमें अपना भोजन अरुचिकर लगता है, हमारी जलवायु ठीक नहीं है हमारे लोग असभ्य हैं तथा हमारी संगति के योग्य नहीं है, हमारी सभ्यता दोषपूर्ण है जबकि विदेशी आकर्षक है अर्थात् संक्षेप में कहें तो हरेक देशी वस्तु खराब है जबकि विदेशी वस्तु लुभावनी है तो मैं नहीं जानता कि स्वराज का क्या अर्थ है? यदि प्रत्येक वस्तु विदेशी ही अपनानी है तो हमारे लिए यह जरूरी होगा कि हम लम्बे समय तक विदेशी संरक्षण में बने रहें क्योंकि विदेशी सभ्यता जनता में व्याप्त नहीं हुई है। मैं ये महसूस करता हूँ कि हम स्वराज को तभी समझ सकते हैं जब हम स्वदेशी के प्रति न सिर्फ लगाव बल्कि अनुराग रखते हों। हमारे प्रत्येक कार्य में स्वदेशी छाप होनी चाहिए। स्वराज तभी मजबूत हो सकता है जब हम यह धारणा रखते हों कि जो कुछ राष्ट्रीय है, कुल मिलाकर वही ठोस है।

– महात्मा गांधी

घटता निर्यात - चिंता का विषय

निर्यातकों का मानना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उनको कम ब्याज दर पर ऋण दिये जाने चाहिए। अभी अधिकांश 10 से 12 फीसद ब्याज दर पर ऋण लेने को बाध्य हैं। यह दर चीन सहित दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। निर्यातक कर्ज की ब्याज दर में दो फीसद की और छूट चाहते हैं।

■ जयंतीलाल भंडारी

भारत का विदेश व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। 2010–11 में यह 132 अरब डॉलर के स्तर पर था जिसके 2011–12 के दौरान 160 से 170 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचने की आशंका है। 2014 तक यह घाटा 278.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है जो 2004 के 14.3 अरब डॉलर के लगभग 20 गुना ज्यादा होगा। अर्थव्यवस्था में पहले से कई चुनौतियां खड़ी हैं। ऐसे में विदेश व्यापार घाटे की चुनौती से निपटना और ज्यादा कठिन दिख रहा है। विदेश व्यापार घाटे के तेजी से बढ़ने का कारण बढ़ता आयात और घटता निर्यात है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने अपनी हालिया अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि यूरोप की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से भारत के आयात बढ़ने और निर्यात घटने की आशंका है। जैसे–जैसे दुनिया फिर से दोहरे वैश्विक व्यापार की ओर बढ़ रही है, वैसे–वैसे वैश्विक व्यापार का आकार कम हो रहा है। विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2012 की रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2012 में घटकर 2.5 फीसद रहेगी। पूर्व में इसके 3.6 फीसद रहने का अनुमान था।

जिस तेजी से तेल का आयात बढ़ रहा है, उसके कारण इस साल 2011–12 में भारत का तेल आयात बिल 80 फीसद तक बढ़ जाएगा। भारत में तेल की खपत का तीन चौथाई आयात किया जाता है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। घटते निर्यात के पीछे अमेरिका और यूरोपीय देशों की बदहाली सबसे बड़ा कारण है।

यूरो जोन देशों की अर्थव्यवस्था के खतरे में होने के कारण भारतीय निर्यात का स्रोत सूख रहा है। नवीनतम सर्वेक्षण बताते हैं कि यूरोप और अमेरिका में लोगों द्वारा खर्च में कटौती से भारतीय निर्यातक मुसीबत में है। भारत के कुल निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत अमेरिका और यूरोपीय बाजार में पहुंचता है।

निर्यात के क्षेत्र में सबसे प्रभावित उद्योग हैं, जेम एंड ज्वैलरी, लेदर, टेक्सटाइल, आईटी, फार्मा आदि। भारतीय निर्यातक संगठनों के संघ (फियो) का मानना है कि वर्ष 2011–12 के दौरान

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने अपनी हालिया अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि यूरोप की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से भारत के आयात बढ़ने और निर्यात घटने की आशंका है। जैसे–जैसे दुनिया फिर से दोहरे वैश्विक व्यापार की ओर बढ़ रही है, वैसे–वैसे वैश्विक व्यापार का आकार कम हो रहा है।

कई देशों में नया निर्यात बाजार खोजने की कवायद की गई है। अफ्रीका और लातिन अमेरिकी देशों में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास हुए हैं। पड़ोसी देशों बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और नेपाल के साथ निर्यात बढ़ाने की कोशिश की गई है। चीन और पाकिस्तान के लिए भी निर्यात बढ़ोतरी के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मंदी के दौर में निर्यात बढ़ाने के ये सभी प्रयास संतोषजनक सिद्ध नहीं हो पाए हैं।

निर्यात के लिए 300 अरब डॉलर का तय लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। वित्त वर्ष की समाप्ति तक निर्यात का आंकड़ा 250–260 अरब डॉलर से ऊपर मांग में कमी, उत्पादन लागत और मजदूरी में बढ़ोतरी की वजह से भारतीय निर्यात क्षेत्र को वैश्विक बाजार में कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके अलावा निर्यातकों पर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर टैक्स बड़ा दबाव है।

निर्यातकों के लिए ड्यूटी एंटाइटलमेंट पास बुक स्कीम खत्म कर दी गई है।

यानी आगामी वित्त वर्ष निर्यातकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक चुनौती वाला होगा। 2012–13 तक निर्यात को 500 अरब डॉलर के निर्धारित लक्ष्य तक ले जाने में भी भारी दिक्कतें आएंगी। विदेशी मुद्रा विनिमय दर में भारी उतार– चढ़ाव दिख रहा है। महंगी ब्याज दरों की वजह से निर्यातकों को ऊंची दर पर कर्ज लेना पड़ रहा है। यद्यपि रुपये के मूल्य में गिरावट की वजह से उन्हें फायदा हुआ है लेकिन इसकी वजह से आयात महंगा हो गया है। इस तरह महंगे ब्याज, गया है। इसमें दो राय नहीं कि विदेश व्यापार घाटा कम करने के लिए देश के वाणिज्य मंत्रालय ने कुछ ऐसे कदम उठाएं हैं, ताकि एक ओर जहां आयात घटे, वहीं निर्यात सेक्टर बेहतर प्रदर्शन में दिखे।

देश की ऑटोमोबाइल, फार्मा– स्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, लेदर, टेक्सटाइल और कई अन्य सेक्टर के निर्यात को बढ़ाने के लिए पहल की गई है। विशेष सेक्टरों मसलन ज्वैलरी एंड जेम्स और टेक्सटाइल की ब्रांड इमेज बेहतर करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन सेक्टरों में प्रशिक्षण और कौशल विकास पर फंड खर्च किए गए हैं।

निर्यात बढ़ाने के लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम करने पर भी ध्यान दिया गया है। कई देशों में नया निर्यात बाजार खोजने की कवायद की गई है। अफ्रीका और लातिन अमेरिकी देशों में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास हुए हैं। पड़ोसी देशों बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और नेपाल के साथ निर्यात बढ़ाने की कोशिश की गई है। चीन और पाकिस्तान के लिए भी निर्यात बढ़ोतरी के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मंदी के दौर में निर्यात बढ़ाने के ये सभी प्रयास संतोषजनक सिद्ध नहीं हो पाए हैं।

फरवरी 2012 के तीसरे सप्ताह में इस्लामाबाद में भारत के वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और पाकिस्तान के गृह मंत्री ए. रहमान मलिक के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के व्यावसायियों को वीजा में ढील देने की जो सहमति बताई है, उसके क्रियान्वयन पर दोनों देशों के बीच निर्यात बढ़ेगा। समाधानस्वरूप मंदी की चुनौतियों के बीच जहां निर्यात बढ़ाने होंगे वहीं आयात नियंत्रित करने की रणनीति बनानी होगी।

निर्यात को दूसरे देशों में दी जा रही सुविधाओं के मद्देनजर प्रोत्साहित करना होगा। विश्व निर्यात बाजार में चीन से मिल रही चुनौतियों का भी सामना करना है। भारत द्वारा निर्यात के नए और वैकल्पिक बाजार की तलाश होनी चाहिए। ब्रिक्स और आसियान देशों में निर्यात बढ़ाने के नए प्रयास करने होंगे। चीन में भी निर्यात की संभावनाएं बढ़ानी होंगी।

माना जा रहा है कि भारत–आसियान मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होने के बाद भारतीय उद्योगों के लिए असीम अवसर पैदा हुए हैं। फिक्की के नवीनतम अध्ययन में खुलासा हुआ है कि भारत आसियान देशों में निर्यात बढ़ा सकता है। इसी तरह खाड़ी देशों में निर्यात संभावनाएं उभर रही हैं। लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भी नई पहल होनी चाहिए। चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिकल रिपब्लिक, पनामा, पेरू और त्रिनिदाद व टोबेगो के साथ भारतीय निर्यातकों के लिए फार्मा, आर्गेनिक केमिकल, व्हीकल, ऑटो पार्ट्स, पेट्रोलियम उत्पाद व टेक्सटाइल क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं।

निर्यातकों का मानना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उनको कम ब्याज दर पर ऋण दिये जाने चाहिए। अभी अधिकांश 10 से 12 फीसद ब्याज दर पर ऋण लेने को बाध्य हैं। यह दर चीन सहित दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। निर्यातक कर्ज की ब्याज दर में दो फीसद की और छूट चाहते हैं। या तो निर्यातकों के लिए ब्याज दर में ही दो फीसद की कटौती कर दी जाए या इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत लाभ दो से बढ़ाकर तीन फीसद कर दिया जाए।

लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए अधिकतम ब्याज दर सीमा सात फीसद और अन्य निर्यातकों के लिए नौ फीसद होनी चाहिए। निर्यातक इकाइयों को सस्ती और सुगम बिजली मिलनी चाहिए। निर्यातकों को करों में रियायत देना होंगी। करेंसी कन्वर्जन पर लगने वाले सेवा कर को समाप्त करने के साथ–साथ विदेशों से मंगाई जाने वाली मशीनरी पर टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) भी खत्म होना चाहिए।

एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) स्कीम का लाभ लेने वाले निर्यातकों को भविष्य में अतिरिक्त निर्यात की बाध्यता से छूट दिए जाने की जरूरत है। इससे निर्यातकों को लागत कम करने में मदद मिलेगी और निर्यात बढ़ेगा।

ईपीसीजी स्कीम के मुताबिक कोई निर्यातक कैपिटल गुड्स का आयात करता है और उस पर शुल्क की छूट लेता है तो उसको अपने कुल निर्यात के अलावा छूट की राशि का आठ गुना अतिरिक्त निर्यात करना पड़ता है। यदि निर्यातकों को सरकार इस प्रकार की शर्त से मुक्त कर दे तो ईपीसीजी स्कीम का फायदा उठाने के लिए कई निर्यातक आगे आएंगे। कड़ी प्रतिस्पर्धा के सामने टिकने के लिए सबसे जरूरी है कि निर्यातक गुणवत्तापूर्ण उत्पादक के रूप में पहचान बनाएं।

अंततः विदेश व्यापार घाटा रोकने के लिए रिजर्व बैंक, सरकार और आयातकों निर्यातकों के संगठनों को बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। सरकार द्वारा आयात कम करने के ठोस उपाय तलाशने होंगे। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

ईरान-इजरायल के बीच फंसा भारत

ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं। वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी कई सदियों से चले आए हैं। अतीत में ऐसे साम्राज्य रहे हैं, जिनका दायरा ईरान से लेकर भारत तक था। आज भले ही भारत इंग्लैंड, अमेरिका या इजरायल के साथ करीबी रिश्ते रखता हो, लेकिन सामाजिक धरातल पर भारत–ईरान संबंधों का इतिहास भारत की कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती. भारत तमाम दबाव के बावजूद खुलेआम उसके विरुद्ध अमेरिका या इजरायल के साथ खड़े होने या दिखने का जोखिम मोल नहीं ले सकता।

■ बालेंदु शर्मा दाधीच

ईरान और इजरायल के आपसी टकराव में नई दिल्ली एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनास्थल बन गया। दोनों ही देशों के बीच आपसी टकराव का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन भारत के साथ दोनों के ही न सिर्फ अच्छे, बल्कि रणनीतिक संबंध हैं। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के वाहन पर हुआ आतंकवादी हमला राजनय और नैतिकता की कसौटियों पर भारत को उलझन में डाल सकता है।

हमले के लिए ईरानी स्रोतों की तरफ इशारा करते खुफिया एजेंसियों के स्पष्ट इनपुट के बावजूद भारत के लिए इस बारे में ईरान से दो टूक बात कर पाना तब तक असंभव ही रहेगा, जब तक कि उसके पास अपने निष्कर्षों के समर्थन में अकाट्य प्रमाण मौजूद न हों। दूसरी ओर पिछले दो दशकों से भारत के करीबी मित्रों में गिना जाने वाला इजराइल यह अपेक्षा करेगा कि एक मित्र देश होने के नाते भारत उसकी जायज चिंताओं पर तटस्थता का रुख न अपनाए।

ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं। वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी कई सदियों से चले आए हैं। अतीत में ऐसे साम्राज्य रहे हैं, जिनका दायरा ईरान से लेकर भारत तक था। आज भले ही भारत इंग्लैंड, अमेरिका या इजरायल के साथ करीबी रिश्ते रखता हो, लेकिन सामाजिक धरातल पर भारत–ईरान संबंधों का इतिहास भारत की कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती।

आज जबकि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अपने चरम पर है तथा इजरायल और ईरान के रिश्ते जंग छिड़ने की हद तक विस्फोटक हो चले हैं। भारत तमाम दबाव के बावजूद खुलेआम उसके विरुद्ध अमेरिका या इजरायल के साथ खड़े होने या दिखने का जोखिम मोल नहीं ले सकता।

अमेरिका इन दिनों भारत को अपने स्वाभाविक सहयोगियों में गिनता है। कई अहम अमेरिकी नेता, अधिकारी और सीनेटर ईरान से कारोबारी संबंध बनाए रखने के लिए भारत की तीखी आलोचना कर चुके हैं।

नई दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद हम पर ईरान से संबंध विच्छेद, कम से कम कारोबारी संबंध विच्छेद करने का दबाव बढ़ जाएगा। अमेरिका में यहूदी लॉबी को बेहद मजबूत माना जाता है और पिछले कई सालों से भारत को उसका समर्थन मिलता रहा है। अभी एक हफ्ते पहले ही अमेरिकन ज्यूइश एसोसिएशन ने अमेरिका में भारतीय राजदूत निरुपमा राव को पत्र लिखकर इस बात पर कड़ी निराशा जताई थी कि एक ओर जहां अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं तथा अमेरिका ईरान की कारोबारी नाकेबंदी करने में जुटा है, वहीं भारत न सिर्फ ईरान

से तेल खरीदने पर अड़िग है, बल्कि आपसी संबंधों का दायरा और बढ़ाने की बात कर रहा है।

ईरान से यूरोपीय कंपनियों की वापसी से पैदा हुए बड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत का एक कारोबारी प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही ईरान जाने वाला है। कभी गरमी, कभी नरमी अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों को आशंका है कि अगर भारत ईरान के विरुद्ध अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को अनदेखा करता रहा तो ओबामा प्रशासन की नजर में वह एक भरोसेमंद रणनीतिक साझीदार नहीं रह जाएगा।

भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में ईरान के विरुद्ध हुए मतदान में ईरान के हक में वोट डाला है। इसके अलावा और भी कई मौकों पर भारत उसके प्रति अपने मित्रतापूर्ण नजरिए को रेखांकित करता रहा है। मौजूदा दौर में भारत ईरान से तेल खरीदने के लिए रुपया आधारित भुगतान की जिस वैकल्पिक प्रणाली का विकास करने में जुटा है, वह भी इसी किस्म की एक मिसाल है।

हालांकि ईरान की ओर से इसी तरह की जवाबी गर्मजोशी हमें कम ही नसीब हुई है। इस्लामी सम्मेलन संगठन में ईरान की मौजूदगी तथा भागीदारी में भी कश्मीर पर भारत विरोधी प्रस्ताव पास होते रहे हैं। वर्ष 2010 में वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी ने कम से कम दो मौकों पर कश्मीरी लोगों को भारत के हाथों प्रताड़ित करार दिया था। तब से भारत और ईरान के रिश्तों में थोड़ा ठंडापन जरूर आया है, लेकिन इतिहास और वर्तमान दोनों से जुड़ी अनिवार्यताएं उन्हें साथ खड़ा कर देती हैं।

ईरान ने दो साल पहले कश्मीर में उन प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के विरोध में भी बयान जारी किया था, जो अमेरिका में कुरान की प्रतियां जलाए जाने से आक्रोश में थे। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वर्ष 2005–06 में जब भारत और अमेरिका के संबंधों में नई गर्मजोशी आई थी और उनके संबंध असैन्य परमाणु करार जैसे मील के पत्थर की ओर बढ़े थे, तब से ही भारत ईरान से संबंधों को लेकर अमेरिकी दबाव में है।

इसी दौर में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी में ईरान के विरुद्ध भी मतदान किया था। इससे ठीक पहले एक अमेरिकी अधिकारी ने बयान दिया था कि इस मुद्दे पर ईरान का साथ देना भारत को भारी पड़ सकता है। भारत–पाकिस्तान–ईरान पाइपलाइन परियोजना भी इसी दौर में भारत की ओर से रद कर दी गई, जिसके लिए अमेरिकी दबाव को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कश्मीर मुद्दे पर भारत के प्रति ईरान के रुख में आया बदलाव संभवतः इन्हीं घटनाओं का नतीजा रहा होगा। राजनीति और कारोबार अमेरिका, इजरायल, इंग्लैंड आदि देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने की इच्छा के बावजूद अगर भारत ईरान के बरक्स दूसरे छोर पर खड़ा दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे ऐतिहासिक तथा भावनात्मक कारणों के अलावा भी बहुत कुछ है।

ऐसा नहीं कि इस्लामी विश्व में भारत के हितों को ईरान से कोई विशेष संरक्षण मिलता हो, लेकिन अफगानिस्तान के संदर्भ में ये दोनों एक–सी ही स्थिति में हैं। भारत के विरुद्ध पनपते आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका और अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के गहरे रिश्ते स्वाभाविक रूप से इस आतंकवादी संगठन को हमारे लिए बड़ी चुनौती बना देते हैं। तालिबान के साथ ईरान के संबंध भी अच्छे नहीं रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के प्रतिद्वंद्वी उत्तरी गठबंधन के साथ रिश्ते मजबूत करने की प्रक्रिया में ईरान का सहयोग लिया था।

आज जबकि पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान तक जमीनी मार्ग मुहैया कराने को तैयार नहीं है तो ईरान अफगानिस्तान तथा पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के लिए भारत का संपर्क–द्वार बन सकता है। बहरहाल, भारत–ईरान संबंधों के राजनीतिक तथा कारोबारी पहलुओं का जिक्र किए बिना इस दोस्ताने को समझना संभव नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों का कारोबार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अहम वह विश्व राजनीति को प्रभावित करने के मामले में है। तमाम दबावों के बावजूद भारत के लिए ऐसे राष्ट्र से कारोबारी संबंध विच्छेद करना संभव नहीं होगा, जो उसके लिए दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम सप्लायर है।

फिलहाल अमेरिका से ऐसे भी बयान आए हैं कि वह भारत–ईरान पेट्रोलियम संबंधों को प्रतिबंधों के दायरे में नहीं गिनता। लेकिन यह तय मानकर चलिए कि ज्यों–ज्यों ईरान के साथ उनका तनाव बढ़ेगा, ऐसी समझ–बूझ कम होती चली जाएगी। दूसरी ओर भारत ईरान के लिए चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। ईरान से संबंधों का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में मुस्लिम मतदाताओं का महत्व और संख्या को देखते हुए भी केंद्र में सत्तारूढ़ दल ईरान, सऊदी अरब तथा दूसरे अहम मुस्लिम राष्ट्रों के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। एक तरफ अमेरिका–इजरायल और दूसरी तरफ ईरान के साथ संबंधों में संतुलन के लिए भारतीय नेताओं को बड़े कौशल की जरूरत पड़ेगी। ❑

केंद्रीय नीति में राज्यों की सहमति जरूरी

जब भी आतंकवाद के विरुद्ध कोई कदम उठाया जाता है तो क्यों वह किसी न किसी विवाद का मुद्दा बन जाता है? इस विसंगति का एक बड़ा कारण यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच न तो लक्ष्य में सहमति होती है और न ही कार्यशैली में सवाल है कि सभी राज्य किसी न किसी सीमा तक आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं। कुछ तो इसके विरुद्ध शून्य सहनशीलता के पक्षधर तक हैं। फिर भी यदि वे केंद्र के कदम का विरोध कर रहे हैं तो केंद्रीय कार्रवाई में ही कोई खोट है. . .

■ जवाहरलाल कौल

हम एक राष्ट्र के रूप में आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में गंभीर क्यों नहीं, जबकि सब जानते हैं कि आतंक का साया आज देश के लगभग हर राज्य पर मंडराने लगा है? जब कभी आतंकवाद का सामना करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो क्यों वह किसी न किसी विवाद का मुद्दा बन जाता है?

इस विसंगति के विभिन्न कारणों में एक बड़ा कारण यह भी है कि केंद्र और राज्यों के बीच न तो लक्ष्य में सहमति होती है और न ही कार्यशैली में। मौजूदा विवाद राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र के गठन पर आरंभ हुआ है। अनेक राज्यों ने आरोप लगाया है कि इस कदम से केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है और देश के संघीय ढांचे को बिगाड़ रही है।

सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि क्या किसी ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जा सके? हम जानते हैं कि हमारे पास कई नियम कायदे हैं, जिनके माध्यम से आज आतंकवाद जैसे अपराधों का सामना किया जाता है। यह भी साफ है कि केंद्र के अतिरिक्त राज्यों के पास भी कई व्यवस्थाएं हैं और इन पर अमल करने के लिए कई संगठन हैं।

ये संगठन जांच गिरफ्तारी और दंड – सबके बारे में हैं लेकिन अक्सर तालमेल के अभाव में कार्रवाई या तो शुरू ही नहीं होती या आरंभ होने पर भी बीच में अटक जाती है।

आतंकवाद संगठित अपराध होता है जो जितना जमीन के ऊपर होता है, उतना ही जमीन के नीचे। आतंकवादी कोई सिरफिरा नहीं होता जो किसी प्रतिशोध की भावना से या किसी व्यक्तिगत जुनून के कारण मारकाट मचाता हो। ऐसे अपराध मानव सभ्यता के आरंभिक दौर से

हम एक राष्ट्र के रूप में आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में गंभीर क्यों नहीं, जबकि सब जानते हैं कि आतंक का साया आज देश के लगभग हर राज्य पर मंडराने लगा है? जब कभी आतंकवाद का सामना करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो क्यों वह किसी न किसी विवाद का मुद्दा बन जाता है?

ही होते रहे हैं। आतंकवाद के पीछे एक विचारधारा होती है और जिससे प्रेरित कुछ संगठन सुनियोजित तरीके से आतंकवाद का इस्तेमाल अपने राजनैतिक या साम्प्रदायिक लक्ष्यों को पाने के लिए लिए समर नीति के रूप में करते हैं।

हमारे देश में आतंकवाद अलगाववादी लक्ष्य पाने के लिए आरम्भ हुआ लेकिन पूर्वोत्तर और कश्मीर के आरंभिक दौर में आतंकवाद के स्वरूप में अब गुणात्मक अंतर आया है। अब यह देशों की प्रतिरक्षा

समरनीति का भी अंग बन गया है। हमारे देश में आतंकवाद पाकिस्तान की भारत विरोधी समरनीति बन चुका है। यानी इसके बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय आयाम खुल गए हैं।

एक चिंताजनक आयाम विभिन्न आतंकवादी गुटों के बीच व्यापक तालमेल के कारण खुल गया है। भारत जैसे विशाल देश में आंचलिक क्षेत्रों में अलगाव की प्रवृत्ति अस्वाभाविक नहीं है। पूर्वोत्तर, पंजाब और कश्मीर के आतंकवादी गुटों के लक्ष्यों में समानता न होते हुए भी एक समानता है कि सबका लक्ष्य भारत राष्ट्र को कमजोर करना है क्योंकि कमजोर भारत में ही उनके उद्देश्य पूरे होने की आशा की जा सकती है। इस एक उद्देश्य के लिए इन संगठनों में समरनीतिक तालमेल पैदा हो गया है। इस तालमेल में विदेशी एजेंसियों की भूमिका भी स्पष्ट है।

विदेशी सहयोग और आर्थिक सहायता से लैस संगठित तंत्र के रूप में आज आतंकवाद भारत संघ के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आतंकवाद राज्यों की सीमाएं नहीं मानता और न ही उसे भारत के संघीय और राज्यों के अधिकारों की चिंता है। ऐसे राष्ट्रव्यापी खतरे का सामना टुकड़ों में नहीं हो सकता है।

विदेशी सहयोग और आर्थिक सहायता से लैस संगठित तंत्र के रूप में आज आतंकवाद भारत संघ के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आतंकवाद राज्यों की सीमाएं नहीं मानता और न ही उसे भारत के संघीय और राज्यों के अधिकारों की चिंता है। ऐसे राष्ट्रव्यापी खतरे का सामना टुकड़ों में नहीं हो सकता है।

सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जयललिता या नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम कि आतंकवाद की पहुंच कहां तक है और उससे निपटने के लिए एक अखिल भारतीय पहल की आवश्यकता है? अगर मालूम है तो क्या यह मान लें कि ये मुख्यमंत्री, जो आतंकवाद विरोधी केंद्र का विरोध कर रहे हैं नहीं चाहते कि राष्ट्र शक्तिशाली रहे?

ये सभी राज्य किसी न किसी सीमा तक आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं और इन में से कुछ तो आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के पक्षधर हैं। फिर भी अगर

अफजल गुरु की याचिका पर जिस तरह सरकार टालमटोल करती रही है, उससे आतंकवाद के प्रति सरकारी गंभीरता पर संदेह स्वाभाविक है। राज्यों के साथ भी केंद्र का रवैया राजनीति प्रेरित रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कदम का विरोध करते हुए कहा कि आतंकवाद हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन जब हमने राज्य में आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित करवाना चाहा तो केंद्र के इशारे पर कई बार राज्यपाल ने उसे अस्वीकार कर दिया।

ये केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं तो क्या माना जाए कि केंद्रीय कार्रवाई में ही कोई खोट है? दरअसल राज्यों को केंद्र सरकार की नीयत पर ही शक है। अपनी विसनीयता खोने के लिए केंद्र सरकार स्वयं उत्तरदायी है।

केंद्र सरकार स्वयं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ईमानदार नहीं दिखती। महत्वपूर्ण मामलों में भी सरकार ने ऐसी धारणा बनाई है कि वह आतंकवादी घटनाओं को दलगत राजनीति के आईने से ही देखती है और कभी–कभी आतंकवादी घटनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल भी करती है। बाटला हाउस कांड के बारे में दोमुंही नीति के कारण लोगों का असमंजस बढ़ गया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सही हैं कि सरकार के गृहमंत्री।

अफजल गुरु की याचिका पर जिस तरह सरकार टालमटोल करती रही है, उससे आतंकवाद के प्रति सरकारी गंभीरता पर संदेह स्वाभाविक है। राज्यों के साथ भी केंद्र का रवैया राजनीति प्रेरित रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कदम का विरोध करते हुए कहा कि आतंकवाद हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन जब हमने राज्य में आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित करवाना चाहा तो केंद्र के इशारे पर कई बार राज्यपाल ने उसे अस्वीकार कर दिया।

अगर राज्य भरोसे लायक नहीं है तो राज्य केंद्र पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। बात अगर केवल नरेंद्र मोदी की ही होती तो गोधरा कांड के बाद दंगों में राज्य सरकार के संदेह के घेरे में आने के कारण केंद्र के व्यवहार को तर्कसंगत ठहराया जा सकता था लेकिन केंद्र की कार्रवाई पर सबसे पहले तो बगावत का झंडा उन ममता बनर्जी ने उठाया जिनकी पार्टी केंद्र सरकार में सहयोगी पार्टी है। उनका साथ दिया ओडिशा के नवीन पटनायक ने, जिन्होंने पिछले चुनाव में ही भाजपा से नाता तोड़ दिया था। नीतीश कुमार, मोदी और जयललिता तो बाद में शामिल हो गए।

केंद्र सरकार स्वयं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ईमानदार नहीं दिखती। महत्वपूर्ण मामलों में भी सरकार ने ऐसी धारणा बनाई है कि वह आतंकवादी घटनाओं को दलगत राजनीति के आईने से ही देखती है और कभी–कभी आतंकवादी घटनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल भी करती है। बाटला हाउस कांड के बारे में दोमुंही नीति के कारण लोगों का असमंजस बढ़ गया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सही हैं कि सरकार के गृहमंत्री।

सबका कहना है कि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल है और इसका केंद्र दुरुपयोग कर सकता है। सवाल है कि क्या नई व्यवस्था का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है? इस केंद्र के गठन का उद्देश्य आतंकवाद के बारे में सारी जानकारियां एक स्थान पर केंद्रित करना है ताकि उचित समय पर इसका उपयोग हो सके। कुछ विदेशी जासूस संगठनों की तरह यह ऐसा संगठन है जिसके पास न केवल जानकारियां हों, अपितु जो आने वाले खतरे को समय रहते भांप भी सके। लेकिन जानकारी संकलन का माध्यम केंद्रीय खुफिया ब्यूरो है। फिर इस संगठन को बिना किसी से पूछे गिरफ्तारी की भी छूट है। इस व्यवस्था के विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में जानकारी संग्रह करने वाला ऐसा कोई जासूसी संगठन नहीं जिसे अपने आप गिरफ्तारी का अधिकार भी हासिल हो। इस व्यवस्था का बेजा इस्तेमाल हो सकता है।

आश्चर्य है कि केंद्र अक्सर विवाद पैदा होने के बाद ही बातचीत आरम्भ करता है। लेकिन देर से ही सही, वार्ता सहभगिता के आधार पर होनी चाहिए ताकि आतंकवाद से लड़ाई दलगत राजनीति का विवाद न बने।

इस मामले में जयललिता का आरोप है कि अनुभव बताता है कि इस संगठन का भी उसी तरह इस्तेमाल हो सकता है जिस तरह केंद्रीय खुफिया ब्यूरो का किया जा रहा है। जयललिता तो इसके खिलाफ अदालत तक पहुंच गई हैं। केंद्र और केंद्रीय सरकार चलाने वाली पार्टी में भरोसे का यह अभाव वर्तमान व्यवस्था लागू करने के बारे में दिखाई देता है।

जिस कदम से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल का संदेह पैदा होता हो, उसमें भी राज्यों से बातचीत किए बिना घोषणा करने के पीछे उसी एकतरफा कार्रवाई की प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसके कारण राज्य और केंद्र सरकार में विश्वास की इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई है। आश्चर्य है कि केंद्र अक्सर विवाद पैदा होने के बाद ही बातचीत आरम्भ करता है। लेकिन देर से ही सही, वार्ता सहभगिता के आधार पर होनी चाहिए ताकि आतंकवाद से लड़ाई दलगत राजनीति का विवाद न बने। ❑

जनता के हक पर मोहर

अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल सही कहा है, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हक के लिए इकट्ठा होना और धरने के माध्यम से प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल पहलू है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लोगों को सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना या किसी भी सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। सरकार को ऐसे अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

■ अरुण जेटली

सुप्रीम कोर्ट ने 4–5 जून, 2011 की रात को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई पुलिस कार्रवाई पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। वैकल्पिक विचार रखना और इनकी स्वीकार्यता के लिए प्रदर्शन करना लोकतंत्र का मूल है।

दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल शुरू किया था। सत्याग्रह का सार अहिंसा के साथ–साथ विरोध भी था। इसकी शक्ति सत्य में निहित है और क्षमता संघर्ष में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को संवैधानिक अधिकार माना है।

अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल सही कहा है, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हक के लिए इकट्ठा होना और धरने के माध्यम से प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल पहलू है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लोगों को सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना या किसी भी सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। सरकार को ऐसे अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। यह सरकार का कर्तव्य है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के भाव का मान रखे, न कि अपनी कार्यपालिका या विधायिका शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनका दमन न करे।'

हालिया अनुभवों से पता चलता है कि राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पुलिस बल प्रयोग का इस्तेमाल करता है। टीम अन्ना को विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली के केंद्र में स्थान हासिल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। विरोध का आकार छोटा रखने के लिए पुलिस की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया।

हालिया अनुभवों से पता चलता है कि राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पुलिस बल प्रयोग का इस्तेमाल करता है। टीम अन्ना को विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली के केंद्र में स्थान हासिल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। विरोध का आकार छोटा रखने के लिए पुलिस की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस प्रकार की हरकतों का संज्ञान लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने से पुष्टि हो जाती है कि बाबा रामदेव और

उनके समर्थकों का प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, 'बाबा रामदेव के समर्थक शांतिपूर्ण ढंग से लाइनों में खड़े थे, जो दो किलोमीटर तक लंबी थी। अगर पुलिस समर्थकों की संख्या पांच हजार तक सीमित रखना चाहती थी तो वह आसानी से समर्थकों को गेट पर ही रोक सकती थी। पुलिस द्वारा इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। पुलिस के आचरण से संकेत मिलता है कि उसे सरकार की तरफ से निर्देश मिले थे।'

अदालत ने कहा कि परिस्थितियों से यह नही लगता कि नियमों का उल्लंघन किया गया था इसलिए पुलिस द्वारा दी गई अनुमति को वापस लेने का कोई कारण नजर नही आता। विद्यमान परिस्थितियों में धारा 144 लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

4–5 जून, 2011 की रात को क्या हुआ था, यह अदालत के अंतिम निर्देश से स्पष्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, 'गृह मंत्रालय से सलाह के बाद या फिर दिल्ली पुलिस का खुद ही रामलीला मैदान में सो रहे लोगों को जबरन हटाने का लिया गया फैसला बिल्कुल अनुचित था और इसमें कुछ हद तक निरंकुशता तथा शक्ति का दुरुपयोग हुआ है. . .सरकार की कार्रवाई राज्य की ताकत का गलत प्रदर्शन है और यह हमारे मूल लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। कोर्ट के समक्ष जो साक्ष्य और परिस्थितियां है, उनसे स्पष्ट है कि रामलीला मैदान में इमरजेंसी के हालात नहीं थे।'

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर सरकार मैदान को खाली भी कराना चाहती थी तो प्रदर्शनकारियों को उचित नोटिस देना चाहिए था। इसके विपरीत सरकार ने गलत तरीके से पुलिस बल का इस्तेमाल किया, पानी की बौछार की, लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस कारण अनेक लोग जख्मी हुए और एक की मौत हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश से जनता के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की और राजनीतिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध की अभिव्यक्ति पर मुहर लगाई। कोर्ट की यह व्यवस्था विरोध के अधिकार की सुरक्षा की पुष्टि करता है और इस बात पर मुहर लगाई है कि लोकतंत्र और विरोध में सहअस्तित्व है।

इस फैसले के लिए कोर्ट सराहना का पात्र है। हालांकि, इसके बाद फैसला विचित्र मोड़ ले लेता है। यह कानूनी व्यवस्था के पालन का दायित्व प्रदर्शनकारियों पर थोप देता है। इस मामले में न तो धारा 144 लागू किया जाना और न ही प्रदर्शन की अनुमति वापस लिया जाना कानूनसम्मत था। प्रदर्शनकारी इस प्रकार के आदेश को क्यों स्वीकार करें।

उन प्रदर्शनकारियों पर किस प्रकार लापरवाही में सहभागिता का सिद्धांत थोपा जा सकता है, जो अपने मूल अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे? इस सिद्धांत का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों को हलका करने में नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों के हनन में इस सिद्धांत को लागू करना पूरी तरह अनुचित है।

भारत ने शांतिपूर्ण संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता हासिल की। असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा और सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के जाने–माने औजार थे। उन्होंने शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता चुना था। सत्याग्रह ऐसा औजार है, जिसमें सत्य के लिए संघर्ष किया जाता है। एक सत्याग्रही दमनकारी सत्ता के विरोध में कानून के उल्लंघन का दंड खुद भोगता है। सत्याग्रही के अधिकार को लापरवाही में सहभागिता के समान मानना लाभ को गंवा देता है। अगर एक प्रदर्शनकारी संवैधानिक अधिकारों के दायरे में शांतिपूर्ण विरोध करता है तो प्रदर्शन न करने के गैरकानूनी आदेश का स्वीकार न करके वह अपने अधिकार का पालन करता है। वह जोखिम उठाता है कि अगर आदेश कानूनी हुआ तो उसे दंडित किया जा सकता है, किंतु जब प्रदर्शनकारी धारा 144 का उल्लंघन करता है तो वह हमेशा दंड को स्वीकार करता है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था से बने कानून के अनुसार जब भी विरोध के उसके मौलिक अधिकार में सरकार दखलंदाजी करेगी उसे तुरंत आदेश का पालन करना होगा, अन्यथा उसे लापरवाही में सहभागिता का दोषी ठहरा दिया जाएगा। अगर राज्य किसी व्यक्ति के विरोध के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है तो महज इस कारण उसे मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ❑

भारत ने शांतिपूर्ण संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता हासिल की। असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा और सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के जाने–माने औजार थे। उन्होंने शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता चुना था। सत्याग्रह ऐसा औजार है, जिसमें सत्य के लिए संघर्ष किया जाता है। एक सत्याग्रही दमनकारी सत्ता के विरोध में कानून के उल्लंघन का दंड खुद भोगता है। सत्याग्रही के अधिकार को लापरवाही में सहभागिता के समान मानना लाभ को गंवा देता है।

हिमालय का विनाशकारी दोहन

1980 में सुंदर लाल बहुगुणा ने हिमालय पर्वतमाला के वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन भी असमय समाप्त हो गया। तब से निर्विहन पेड़ें की कटाई और पहाड़ों की बेतरतीब छंटाई जारी है। हालांकि बिना सरकारी परमिट के वृक्ष काटना संभव नहीं है लेकिन सरकारी कानून में असंख्य छिद्र होने के कारण गैर–कानूनी तरीका से मूल्यवान पेड़ों का संहार किया जा रहा है।

■ उमेश प्रसाद सिंह

हिमालय बचाओ का नारा पहली बार डॉ. राममनोहर लोहिया ने 1950 में दिया था। उस समय लोहिया जी को जन समर्थन नहीं मिला। आज स्थिति यह है कि भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान तक हिमालय पर्वत श्रृंखला का प्राकृतिक संतुलन भू–स्खलन के कारण काफी बिगड़ गया है। पर्वत के अनेक हिस्सों में पहाड़ टूट–टूटकर गिर गए हैं। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई किया जाना है। नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों की धोड़ाई भी काफी बढ़ गई है। जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और भूमिगत जल भंडार में भी कमी होने लगी है।

यहां की स्थिति को देखते हुए 1980 में सुंदर लाल बहुगुणा ने हिमालय पर्वतमाला के वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन भी असमय समाप्त हो गया। तब से निर्विहन पेड़ें की कटाई और पहाड़ों की बेतरतीब छंटाई जारी है।

हालांकि बिना सरकारी परमिट के वृक्ष काटना संभव नहीं है लेकिन सरकारी कानून में असंख्य छिद्र होने के कारण गैर–कानूनी तरीका से मूल्यवान पेड़ों का संहार किया जा रहा है।

हिमालय का पश्चिमी भाग जो अफगानिस्तान और कुछ पाकिस्तान में है एकदम वृक्षविहीन हो चुका है। यहां मरूस्थल जैसा क्षेत्र बन गया है। इधर नंगा पहाड़ (पाक–कश्मीर) से लेकर म्यामार की सीमा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लम्बी दूरी तक हिमालय का विनाशकारी दोहन जारी है।

यहां एक तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं दूसरी ओर बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष पहाड़ों पर यात्रा करने वाले पर्यटकों द्वारा फेंके गए कचरे से भी प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। जापान के प्रोफेसर कोजी फूजिता के अनुसार हिमालय का ग्लेशियर एक मीटर

वृक्षों के विनाश का एक बड़ा कारण हिमालय क्षेत्र में जनसंख्या का विस्तार भी है। पिछले कुछ वर्षों में इस पर्वतमाला पर तीन सौ मीटर की ऊंचाई तक आबादी बढ़ गई है। इस काल में सम्पूर्ण हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र में लगभग सात करोड़ लोगों ने अपना बसेरा बनाया। इनके रोजगार का मुख्य साधन पुशपालन, जंगली जीवों की हत्याकर उनके शरीर का अवशेष बेचना, वनों से लकड़ी काटकर नीचे के गांवों में बेचना और जड़ी–बूटी के नाम पर पौधों को उखाड़ना है।

प्रतिवर्ष घट रहा है। उनका कहना है कि पहले हिमालय चारों ओर से सफेद रंग ओढ़े हुए बर्फीले पहाड़ थे। लेकिन अब यहां नालानुमा मैली पिघलती बदशक्ल बर्फ दिखायी देती है।

नेपाल की स्थिति तो और ही बदतर है। विश्व में सबसे ज्यादा लकड़ी नेपाल में जलाई जाती है। यहां लकड़ी स्थानीय खेतों में पैदा नहीं होती बल्कि हिमालय में फैले जंगलों से काटी जाती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं संस्कृति संगठन द्वारा नेपाल में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि नेपाल में प्रतिवर्ष 70 लाख टन लकड़ी ईंधन के रूप में जला दी जाती है।

हिमालय पर आए संकट के कारण कुछ नदियों पर खतरा हो सकता है। हिमानी पिघलाव का यह रफ्तार जारी रहा तो अगले 50–60 वर्षों में गंगा, गंडक सरयू और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इतिहास का विषय बन सकती हैं।

वृक्षों के विनाश का एक बड़ा कारण हिमालय क्षेत्र में जनसंख्या का विस्तार भी है। पिछले कुछ वर्षों में इस पर्वतमाला पर तीन सौ मीटर की ऊंचाई तक आबादी बढ़ गई है। इस काल में सम्पूर्ण हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र में लगभग सात करोड़ लोगों ने अपना बसेरा बनाया। इनके रोजगार का मुख्य साधन पशुपालन, जंगली जीवों की हत्याकर उनके शरीर का अवशेष बेचना, वनों से लकड़ी काटकर नीचे के गांवों में बेचना और जड़ी–बूटी के नाम पर पौधों को उखाड़ना है। स्थानीय निवासी यहां बड़ी मात्रा में पत्थर काटने वाले माफियाओं का सहयोग करते हैं। इनके असंख्य पशु चोटियों पर पहुंचकर वृक्षों को चट कर जाते हैं। यहां के निवासियों के लिए ईंधन का प्रमुख स्रोत लकड़ी है। अधिकांश लकड़ी रात के अंधेरे में या वन विभाग के अधिकारियों से मिलजुल कर काटा जाता है। यहां के चरवाहे ग्रुप बनाकर वन–पशुओं को घेरकर उनकी हत्या करते हैं।

हिमालय की तलहटी में बसे राज्यों में उत्तराखण्ड प्रमुख है। लगभग 75 वर्ष पूर्व तक यहां का 85 प्रतिशत क्षेत्र वनोच्छादित था। अब यहां 25–26 प्रतिशत क्षेत्रों में वन है। पर्यावरण संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने मनाली से लेकर रोहतांग तक के इलाके में किसी तरह का निर्माण कार्य पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। हालांकि पहाड़ी वनवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के जमीन–जायदाद खरीदने पर पहले से ही पाबंदी है लेकिन राज्य सरकारें अधिक राजस्व वसूलने के चक्कर में नियमों की अनदेखी कर देती है।

हिमाचल हाईकोर्ट ने मनाली से लेकर रोहतांग तक के इलाके में किसी तरह का निर्माण कार्य पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। हालांकि पहाड़ी वनवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के जमीन–जायदाद खरीदने पर पहले से ही पाबंदी है लेकिन राज्य सरकारें अधिक राजस्व वसूलने के चक्कर में नियमों की अनदेखी कर देती है।

इसका परिणाम यह है कि भवन निर्माण कंपनियां यहां धड़ल्ले से भवन बना रही हैं। देशभर में जिस तेजी से पक्के मकान बन रहे हैं, उनके लिए रोड़ी, सीमेण्ट और पत्थर के कटान का मुख्य केन्द्र हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। यहां बारूद लगाकर पत्थर को तोड़ा जाता है। इससे दूर–दूर तक पर्वतीय क्षेत्र हिल जाता है।

वन नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रह सकता। विश्व का सिरमौर पर्वत श्रृंखला नंगा होता जा रहा है। वन रोपन करते समय स्थानीय लोगों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वे पीढ़ियों से वनों का सहचर रहे हैं।

हिमालय पर चीन, नेपाल और भारत में सड़क निर्माण का होड़ मचा है इससे भी यह पर्वतमाला प्रभावित हो रहा है। कानून के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी योजना शुरू करने से पूर्व स्थानीय पंचायत की स्वीकृति आवश्यक है परंतु पंचायतों पर दबाव बनाना बहुत आसान कार्य है। हाईकोर्ट के आदेशों का यहां अवमानना हो रहा है।

नेपाल की स्थिति तो और ही बदतर है। विश्व में सबसे ज्यादा लकड़ी नेपाल में जलाई जाती है। यहां लकड़ी स्थानीय खेतों में पैदा नहीं होती बल्कि हिमालय में फैले जंगलों से काटी जाती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं संस्कृति संगठन द्वारा नेपाल में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि नेपाल में प्रतिवर्ष 70 लाख टन लकड़ी ईंधन के रूप में जला दी जाती है। नेपाल में स्थित काली के जंगल में 90 प्रतिशत वृक्ष केवल घरेलू ईंधन के लिए काट लिए गए हैं अब नेपाल देश के अंतरिम भाग में सिर्फ 20 प्रतिशत क्षेत्र में वन रह गए हैं?

अरुणाचल प्रदेश हिमालय की गोदी में बसा एक प्रमुख राज्य है। इस राज्य का 1030 किलोमीटर की सीमा चीन से मिलती है। यहां प्रकृति ने दोनों हाथों से सौन्दर्य लुटाया है। इस भूमि पर प्रवाहित होने वाली कुल 50 नदियां प्रदेश के लिए वरदान है। अरुणाचल प्रदेश में 51,540 वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र है। इनमें 9615 वर्ग किलोमीटर आरक्षित है।

यहां के जंगलों में दो सौ मिले लाइसेंससुदा है। ये मिलें लकड़ी पर आधारित हैं। इसलिए इन्हें लकड़ियां दी जाती है। ट्री परमिट पर इन्हें 45 लाख घन मीटर लकड़ी प्रतिवर्ष दी जाती है। लेकिन वन अधिकारियों से मिलकर ट्री परमिट का दुरूपयोग करते हैं और मनचाहे ढंग से पेड़ों को काटते हैं।

वनों की रक्षा के लिए अनेक कानून बने हैं लेकिन कानून बनाने या संरक्षण देने से वन सुरक्षित नहीं रहे सकते। जनता के समर्थन और सहयोग के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। जो क्षेत्र वनविहीन हो गए हैं उन्हें फिर से हरा भरा बनाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। वन के अभाव, पहाड़ों का कटाव सड़क और रेल लाइन का निर्माण जैसे मानवीय हस्तक्षेप के कारण वनों का विनाश हुआ है।

वन नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रह सकता। विश्व का सिरमोर पर्वत श्रृंखला नंगा होता जा रहा है। वन रोपन करते समय स्थानीय लोगों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वे पीढ़ियों से वनों का सहचर रहे है। पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत आम, महुआ, सहतूत जैसे पेड़ों के अतिरिक्त ओक और रेजिन जैसे वृक्ष बहुत उपयोगी है। ओक से पशुओं का चारा मिलता है। इसकी पत्तियां भूमि में नमी बनाए रखती हैं। रेजिन से तारपीन का तेल बनता है जिसकी मांग देश के विभिन्न भागों में है।

हिमालय के विभिन्न चोटियों पर चढ़ने वाले अभियान दल से भी यहां कम खतरा नहीं है। अकेले एवरेस्ट मार्ग पर पन्द्रह हजार किलोग्राम से अधिक कचरा पड़ा हुआ है। इसमें सर्वाधिक पोलिथीन है। जबकि एवरेस्ट का मार्ग सबसे कठिन है। कुछ वर्ष पूर्व छपी एक रपट से पता चलता है कि चीन अपने एटमी कचरे को तिब्बत में दफनाता है। इससे वहां के पक्षी और बाकी जीव-जंतु प्रभावित होते हैं। धरती की रक्षा करनी है तो हमें पहले हिमालय पहाड़ को बचाना होगा। ❑

भारत की आत्मा गाँव है एवं गाँव की आत्मा कृषक

यात्रा से जाना कि वनवासी किस प्रकार अपने घर कच्ची मिट्टी से बनाते हैं, पत्थरों को मिट्टी से जोड़ते हैं तथा जो थोड़े समर्थ होते है वे उन कच्ची दीवारों पर सीमेण्ट का लेप कर देते हैं। छत के ऊपर केलू (मिट्टी का पका कर बनाए हुए) जो भरी गर्मी में भी तपते नहीं ठंडे रहते हैं लगे हुए है। एक ओर हम है जो गर्मियों में ए.सी. एवं कूलर के आदि हो गए हैं जिससे प्रकृति का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और दूसरी ओर ये वनवासी बंधु जो प्रकृति की गोद में संतोष की नींद लेते हैं।

■ डॉ. नन्द सिंह नरूका

बात उन दिनों की है जब भारतवर्ष में विश्वमंगल गो ग्राम यात्रा चल रही थी। मैं उन दिनों खेखाड़ा महाविद्यालय में व्याख्याता लगा हुआ था। खेखाड़ा तहसील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित वनवासी बाहुल्य क्षेत्र है जो उदयपुर से अहमदाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर 85 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है।

विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा के निमित खेखाड़ा तहसील के कार्यकर्ता श्री क्रांतिलाल मीणा जो एक अध्यापक है के साथ मैं सायंकाल 5 बजे उनकी मोटर साइकिल पर ग्राम सम्पर्क के लिए निकला। खेखाड़ा उपखण्ड के उत्तर–पश्चिमी भाग के गांवों की ओर गए।

मुख्य सड़क अच्छी बनी हुई थी। सड़क पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण कहीं नीचे की ओर जा रही थी तो कहीं ऊंचे की ओर कभी सर्पाकार में बाँयी ओर घूम रही थी तो कहीं दाई ओर।

कुछ दूरी इसी प्रकार तय की। इस सड़क को छोड़कर अब जिन गाँवों की ओर हमें जाना था उस ओर हम मुड़े। आगे का रास्ता कठिन था। उबड़–खाबड़ रास्ते, जगह–जगह रास्ते में पहाड़ी पत्थर के टुकड़े। उनके ऊपर होकर हमारी मोटर साईकिल जा रही थी। पूरा क्षेत्र पहाड़ी एक नहीं अनेक पहाड़ियां, पहाड़ियों के अलग–अलग भाग में वनवासी बन्धुओं के घर। पहाड़ियों के मध्य में सकड़ी–सकड़ी जगह उन्हीं में वनवासियों के खेतों के टुकड़े। खेत चौकोर नहीं पहाड़ियों के बीच–बीच जैसी आड़ी–तिरछी जगह मिली उसी अनुरूप वनवासियों ने अपने खेत बना लिए।

सर्वप्रथम हम कारछा खुर्द गाँव गए। यहां पूर्व उपप्रधान श्री अमृत पटेल से मिलना हुआ। पटेल के समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, तीन बैलों से बावल के खलियान पर गायटा (भूसे पर बैलों की केलू की तरह जोतना) कर रहे थे। सभ्य प्रतिष्ठित व्यक्ति परंतु काम की नहीं शर्म नही। हम शहरी होते तो क्या इस प्रकार का काम कर पाते? अपनी झूठी शान में काम से नफरत करते। वहां हमने गो–ग्राम यात्रा का महत्व बतलाया, हस्ताक्षर हेतु समझाया। उन्होंने पूर्ण तन–मन–धन से सहयोग करने के लिए हमें आश्वस्त किया।

आगे फिर हम दूसरे अगले गाँव लराठी गए। इस गाँव में जहाँ हमें जाना था। वहां मोटर साईकिल भी नहीं जा सकती थी। हम मोटर साईकिल एक वनवासी सज्जन के घर छोड़कर पैदल ही निकले। कुछ दूरी तक पहाड़ी क्षेत्र में नीचे–ऊपर चलते–चलते पन्ना लाल जी के घर पहुँचे।

वनवासियों की एक अलग ही प्रथा

है, जब मिलते हैं तो बिना किसी ऊँच–नीच, स्त्री–पुरुष के भेदभाव किए हाथ मिलाते हैं। हमने भी उनसे हाथ मिलाया। उनकी खाट पर बैठे। विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा अभियान में हस्ताक्षर कार्य में सहयोग हेतु निवेदन किया तो वे सज्जन सहज तैयार हो गए।

श्री पन्ना लाल जी से विदा लेकर हम पुनः अपनी मोटर साईकिल से आगे क्रांति जी जो उसी गाँव के रहने वाले है के माता–पिता के घर के लिए चल दिए। यह रास्ता और भी अधिक पहाड़ी क्षेत्र में तथा पत्थरीला था। क्रांति जी को इन रास्तों पर चलने का अभ्यास था अतः बिना संकोच आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में क्रांति जी के भाई कालूराम जी के खेत पर मोटर साईकिल रखी और क्रांति जी के माता–पिता से मिलने पैदल चल पड़े।

क्रांति जी के माता–पिता पहाड़ी के ऊपर घर बना कर रहते हैं। वृद्ध पिताजी गुदा व दमा रोग से पीड़ित थे उनसे मिलना हुआ। वहाँ माताजी ने एक डिब्बे में भैंस का दूध दिया उसे लेकर क्रांति जी के घर के लिए निकल पड़े।

क्रांति जी के घर जाते समय अंधेरा हो गया था। पास में तालाब बना हुआ था, उसकी नहर के किनारे से होकर मोटर–साईकिल से जा रहे थे। बहुत सकड़ा रास्ता कहीं चढ़ाई, पत्थर गिरे हुए थे लगता था कहीं थोड़ी चूक हुई और गिरे नहर में।

क्रांति जी कह रहे थे इस जंगल में बघेरा भी है, थोड़ी दूर में ही मांस हड्डियों के सड़ान्द की बदबू आई। यहीं पर बघेरा जंगली पशुओं को मारकर खाता है। ऊबड़–खाबड़, सकरे पत्थरीले रास्ते से होते हुए क्रांति जी के घर पहुँचे।

क्रांति जी का घर उनके माता–पिता

श्री पन्ना लाल जी से विदा लेकर हम पुनः अपनी मोटर साईकिल से आगे क्रांति जी जो उसी गाँव के रहने वाले है के माता–पिता के घर के लिए चल दिए। यह रास्ता और भी अधिक पहाड़ी क्षेत्र में तथा पत्थरीला था। क्रांति जी को इन रास्तों पर चलने का अभ्यास था अतः बिना संकोच आगे बढ़ रहे थे।

के घर से 2 किलोमीटर दूर अलग ही बनाया हुआ था। जनजातियों में यह अजब ही प्रथा है कि शादी होते ही लडत्रके को अलग कर दिया जाता है कि अब तुम अपनी गृहस्थी अलग से चलाओ।

क्रांति जी के घर के पर केवल उनकी परित्यक्ता बुआ (रूप जी) रहती थी। उनकी बुआ से वार्ता की न तो बुआ मेरी भाषा समझ सकी और न ही मैं उनकी बागड़ी भाषा समझ सका। परंतु अपनेपन का भान ऐसा लगा जैसे इस जंगल में भगवान शबरी यही है। अकेले मैं कैसे समय निकलता है तो पता लगा एक पालतू बिल्ली है, गाय का बछड़ा है उन्हीं से मन लग जाता है। घोर जंगल में अकेले रहना काहे का डर एक ओर हम है जिन्हें थोड़े से अंधेरे में ही डर सताने लगता है। धिक्कार है हमारे शहरीपन को।

क्रांति जी ने चूल्हे पर हमारे लिए उड़द की दाल बनाई तथा उनकी बुआ ने मेरे लिए मक्के की रोटी बनाई। शुद्ध ताजा गाय के घी के साथ मक्के की रोटी एवं उड़द की दाल से भोजन किया। उसके बाद गाय के शुद्ध दूध का सेवन कर चल पड़े पुनः शहर की ओर लौटने के लिए।

घूप–अंधेरा, सांय–सांय की आवाज चुपचाप लोट रहे थे। वही नहर के किनारे, फिर उबड़–खाबड़ रास्ते से चले आ रहे थे। मार्ग में बाबू लाल जी अध्यापक के घर रुके उन्हें भी विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा तथा हस्ताक्षर अभियान के बारे में बतलाया, उनका लड़का भी कार्यकर्ता था उसने भी सहयोग देने के लिए कहा। फिर घूप अंधेरे में ही आगे बढ़े रास्ते में एक और अध्यापक व वरिष्ठ लिपिक रामलाल जी धुनकर का घर था अपने आने का कारण बतलाया, उन्होंने भी पूर्ण सहयोग देने को कहा।

लगता था जैसे गाँव एवं गाय का चोली दामन का साथ है किसी ने भी असहयोग नहीं दिखाया। गोकर्ण पीठ के राघवाचार्य जी का कहना ठीक ही है कि भारत की आत्मा गाँव है एवं गाँव की आत्मा कृषक व कृषक की आत्मा गाय।

यात्रा से जाना कि वनवासी किस प्रकार अपने घर कच्ची मिट्टी से बनाते है, पत्थरों को मिट्टी से जोड़ते है तथा जो थोड़े समर्थ होते है वे उन कच्ची दीवारों पर सीमेण्ट का लेप कर देते हैं। छत के ऊपर केलू (मिट्टी का पका कर बनाए हुए) जो भरी गर्मी में भी तपते नहीं ठंडे रहते हैं लगे हुए है। एक ओर हम है जो गर्मियों में ए.सी. एवं कूलर के आदि हो गए हैं जिससे प्रकृति का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और दूसरी ओर ये वनवासी बंधु जो प्रकृति की गोद में संतोष की नींद लेते हैं। धन्य है ये लोग। यदि इनकी कुरीतियों तथा व्यसन का अंत हो जावे तो यहीं स्वर्ग है समझो। हम भी धन्य हुए इनकी जिन्दगी को समझकर। इस प्रकार हमारी यात्रा पूर्ण हुई। ❑

महिला शिक्षा और विकास

हमारे धर्म–ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी और राजनैतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहती थी। सन 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार गुणात्मक सुधार हुआ, परंतु किसी की दृष्टि से इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। भारत में महिला शिक्षा की प्रगति बहुत ही धीमी गति से हुई है।

■ रेणु पुराणिक

भारत की सभ्यता और संस्कृति अत्याधिक पुरानी है और समय के साथ–साथ हमारी संस्कृति में बहुत उतार–चढ़ाव भी आए हैं। इन्हीं उतार–चढ़ाव के कारण भारतीय परंपरा में जिज्ञासा की भावना को बल मिला। प्राचीन भारत में मौखिक संस्कृति के माध्यम से ज्ञान का प्रसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता था। वैदिक युग से लेकर आज के आधुनिक युग तक भारत में ज्ञान एवं शिक्षा के प्रसार–प्रचार में अनेकों विविधताएँ देखी जा सकती है, परंतु एक बात जो हमेशा अपरिवर्तित रही है, वह है महिलाओं में ज्ञान एवं शिक्षा के प्रसार–प्रचार की कमी। शिक्षा को किसी भी वर्ग के विकास का पैमाना माना जा सकता है। दुनियाभर में देखा जाए तो, जहाँ अधिक शिक्षित लोग है, वही का विकास अधिक हुआ है तथा वे ही देश आज विकास की दौड़ में सबसे आगे हैं – जहाँ शिक्षा का प्रतिशत अधिक है।

शिक्षा को अपने आपमें साध्य तथा अन्य वाँछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का साधन माना जाता है। शिक्षा से ही व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और उसका व्यक्तित्व निखरता है। व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ ही उसमें सांस्कृतिक समझ भी विकसित होती है। शिक्षा के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है और समाज में गतिशीलता आती है।

शिक्षा को अपने आपमें साध्य तथा अन्य वाँछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का साधन माना जाता है। शिक्षा से ही व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और उसका व्यक्तित्व निखरता है। व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ ही उसमें सांस्कृतिक समझ भी विकसित होती है। शिक्षा के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है और समाज में गतिशीलता आती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग के लिए शिक्षा अति–आवश्यक है तथा महिलाओं के लिए इसका महत्व अधिक ही है। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जो नयी समाज व्यवस्था का सृजन करने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाता है।

हमारी सभ्यता और संस्कृति की महानता है कि हमारे वेदों में महिला–शिक्षा का विशद वर्णन किया गया है। सभी चारों वेदों में महिला संबंधी हजारों मंत्र दिए है, जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक काल में महिलाएं समाज में विशेष स्थान पर प्रतिष्ठित थी। यजुर्वेद के अनुसार वैदिक

काल में महिलाओं को वेद अध्ययन का अधिकार था और बालिका भी बालको के समान ही शिक्षा ग्रहण करती थी।

ऋग्वेद में तो कहा गया है कि महिलाओं पर ही जीवन आधारित है और वे ही समाज के अन्य वर्गों को शिक्षा प्रदान करती है। वैदिक साहित्य में सूर्या, सावित्री, सिकता, निरावरी, रोमिषा, लोपामित्रा, इन्द्राणी, गार्गी एवं आत्रेयी आदि 29 विदूषी महिलाओं का वर्णन किया गया है।

हमारे धर्म–ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी और राजनैतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहती थी।

सन 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार गुणात्मक सुधार हुआ, परंतु किसी की दृष्टि से इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। भारत में महिला शिक्षा की प्रगति बहुत ही धीमी गति से हुई है।

वास्तव में भारत में अनेक ऐसे सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण है जिनके कारण महिलाएं शिक्षा प्रणाली में भाग नहीं ले पाती है। समाज में लड़कियों के संदर्भ में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों तथा घरेलू कार्यों का प्रजनन में महिलाओं की भूमिका के कारण भी महिला शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(1) बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए उपेक्षाभाव।
(2) युवा लड़कियों पर अनेक प्रतिबंध।
(3) कम उम्र में लड़कियों का विवाह।
(4) कम उम्र में माँ बनने की जिम्मेदारी का निवर्हन।

(5) लड़के और लड़कियों में भेदभाव।
(6) महिलाओं में शिक्षा के प्रति चेतना की कमी।
(7) गरीबी एवं सुविधाओं का अभाव।
(8) ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल व कालेजों का अभाव।
(9) विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण।
(10) सरकार की महिला–शिक्षा के प्रति उदासीनता।

उपरोक्त कारणों से भी महिला शिक्षा की राह में बाधाये आने से उनकी स्थिति में सुधार नहीं आ पाता है।

शिक्षा की कमी के कारण भी आज महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाती है। वे मेहनत पूर्णतः करती है, परंतु देश के आर्थिक नियोजन में उनकी कोई भागीदारी नहीं है।

महानगरों मे कुछ मुट्ठी भर महिलाओं की बात यदि छोड़ दें, तो भारत की अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से परतंत्र ही है। वे स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि उनके पास आर्थिक साधन नहीं है।

साक्षरता को किसी भी समाज में सामाजिक व आर्थिक विकास का प्रतीक

विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर लड़के–लड़कियों का प्रतिशत

शिक्षा का स्तर/प्रकार	लड़को का प्रतिशत	लड़कियों का प्रतिशत
पी.एच.डी./एम.फिल	73.9	26.1
एम.ए	62.2	37.8
एम.एस.सी.	68.4	31.6
बी.ए.	64.2	35.8
बी.एस.सी.	73.2	26.8
बी.एड./बी.टी.सी.	59.1	40.9
एम.बी.बी.एस.	75.7	24.3
बी.काम.	86.0	14.0
बी.ई.(इंजी)	96.5	3.5
तकनीकी	80.9	19.1

माना जाता है। सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक चेतना तथा आर्थिक विकास के लिए उच्च साक्षरता दर और शिक्षा की गुणवत्ता परम आवश्यक है परंतु भारत दोनों ही मोर्चों पर बहुत पिछड़ा हुआ है।

भारत में महिला शिक्षा या महिला साक्षरता की मीमांसा करने से पूर्व भारतीय जनगणना विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। सन 1951 में देश में साक्षरता दर मात्र 18.33 प्रतिशत ही थी, लेकिन सन 2011 में यह दर 71.70 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान में देश के 80.50 प्रतिशत पुरुष और 62.30 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। सन 1951 में महिला साक्षरता मात्र 8.86 प्रतिशत ही थी।

विभिन्न सरकारी प्रयासों के कारण आज महिला शिक्षा की दिशा में बहुत प्रगति हुई है, परंतु यह प्रगति की चमक महानगरों और शहरों तक ही सीमित है। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में तो आज की स्थिति बहुत निराशाजनक है। कस्बों और गाँवों में महिलाएं आज भी कला व वाणिज्य विषय ही पढ़ने पर बाध्य रहती है, किन्तु महानगरों और शहरों में महिलाएं वाणिज्य, प्रबंधन, तकनीकी और जनसंचार जैसे आधुनिक विषय अधिक पढ़ रही है तथा तकनीकी प्रशिक्षण व औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है।

शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता व संस्कृति के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ-प्रदर्शन करती है। विद्वानों का मत है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है और यह तीसरा नेत्र समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा से हमें एक ऐसे प्रकाश की प्राप्ति होती है जो हमारे सभी प्रकार के संशयों का उन्मूलन कर देता है। शिक्षा से हमें सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है जिसके कारण हमारी बुद्धि, विवेक, कौशल और निपुणता में वृद्धि होती है। यह शिक्षा का ही महत्व है कि भारतीय विद्वान भर्तृहरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'नीति शतक' में कहा है – विद्या-विनयहीन मनुष्य, पशु के समान है। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के ऊपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/-	1000/-
अंग्रेजी	100/-	1000/-

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22

स्वदेशी परिवार सम्मेलन (जमशेदपुर)

भारत वर्ष में एक और जहाँ परिवार बिखर रहें हैं वहाँ स्वदेशी परिवार सम्मेलन करना स्वदेशी जागरण मंच का सराहनीय कदम है – डॉ. गोस्वामी

29 जनवरी 2012 को स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर का परिवार मिलन सह वनभोज का आयोजन गाँधी घाट मानगो में हुआ।

इस परिवार मिलन में अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. दिनेशानन्द गोस्वामी, पूर्व विधायक सरयू राय तथा स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक विनोद कुमार सिंह उपस्थित थे। उपस्थित लगों को संबोधित करते हुए डॉ. गोस्वामी ने कहा की भारत वर्ष में एक और जहाँ परिवार बिखर रहें हैं वहाँ स्वदेशी परिवार सम्मेलन करना स्वदेशी जागरण मंच का सराहनीय कदम है।

पूर्व विधायक सरयूराय ने कहा की स्वदेशी जागरण मंच का यह कार्यक्रम बिखरते परिवारों को इक्कठा करने में संजीवनी का काम करेगा। जबतक इस देश के लोगों ने इस देश को अपना एवं यहाँ रहने वालों को अपना परिवार समझा देश हर तरह से संपन्न रहा। लेकिन जब से लोगों ने अपनी संस्कृति और परिवारिक भाव को छोड़ा देश में बिखराव और परिवारों में समन्वय का अभाव दिखने लगा। क्षेत्रीय संयोजक श्री विनोद कुमार ने भारतवर्ष में परिवारों की कल्पना उसका इतिहास, आदेश परिवार और आज के संदर्भ में संयुक्त परिवार की आवश्यकता के बारे में विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में बन्देशंकर सिंह और बोकारो से आये कौशल किशोर ने भी अपने विचार रखे।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनिल राय और धन्यवाद ज्ञापन राजकुमार साह ने किया। इस अवसर पर महिलाओं और बच्चों के लिए खेल का भी आयोजन किया गया था। ❑

डॉ. दिवाकर बोकरे के रूप में स्वदेशी के प्रभावी भाष्यकार को खोया
विनम्र श्रद्धांजलि

स्वदेशी जागरण मंच, राष्ट्रीय परिषद सदस्य श्री दिवाकर बोकरे का गत दिनों पुणे में हृदयगति रूकने से निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। दिल्ली में आयोजित प्रांत संयोजकों की बैठक में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण ओझा ने श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता की।

नागपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्र–कुलगुरु प्राचार्य योगानंद काले ने अपने विचार रखे। श्री काले ने कहा कि दिवाकर जी बोकरे ने चार्टर्ड एकाउंटेंट के नाते महिन्द्र एण्ड महिन्द्र कंपनी में अपनी सेवा प्रदान की। वे कंपनी के उपाध्यक्ष (वित्त) रहे। इस दायित्व से उन्होंने विश्व के अनेक देशों में प्रवास किया। विश्व के अनेक कार्पोरेटस की कार्यशैली से वे सुपरिचित थे। अपने ज्येष्ठ बंधु एवं मंच के संस्थापक संयोजक डॉ. मधुकर बोकरे के हिन्दू अर्थशास्त्र एवं अन्य ग्रंथों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। कार्पोरेट जगत में वर्षों काम करने के पश्चात भी आर्थिक क्षेत्र का हिन्दू दृष्टिकोण ही विश्व का भावी रास्ता होना चाहिए ऐसा उनका मत था। इस मत का उन्होंने पुणे, मुंबई के अनेक परिषदों में प्रभावी प्रतिपादन किया।

डॉ. मधुकर बोकरे द्वारा लिखित तथा अप्रकाशित आर्थिक साहित्य का उन्होंने प्रकाशन किया। दिनांक 22 एवं 23 फरवरी को उनके प्रयासों से पुणे के गरवारे महाविद्यालय में हिन्दू अर्थशास्त्र इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 250 की संख्या में शिक्षाविद, उद्योजक एवं पदव्युत्तर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों ने उपस्थिति के लिए पंजीयन कराया था। किंतु इसके तीन दिन पूर्व ही डॉ. दिवाकर बोकरे ने अंतिम सांस ली।